CNEWS मिटी चीफ

मिटी चीफ

वर्ष-17, अंक-202 पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सम्पूर्ण भारत में चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, बुधवार 04 नवंबर 2026



न्यूज अपटेड

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ घूस मामले में जांच के आदेश

तिरुवनंतपुरम। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच होगी। केरलम के गृहमंत्री मेश चेन्निथला ने विजिलेंस को जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़ा है। उस समय ज्ञानेश कुमार राज्य में लोनिवि के सचिव थे। कोल्लम के ठेकेदार साजन का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद पेमेंट करने के बदले 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। इस समय कांग्रेस की अगुवाई में पूरे देश में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीएफ ने 140 में से 97 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने यहां 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है।

जलपरी शो में टूटा शीशे का टैंक

बहराइच। उत्तरप्रदेश के बहराइच के फखरपुर क्षेत्र के खालिदपुर गांव में आयोजित दादा मियां के उर्स मेले में शो के लिए बनाए गए पानी से भरे टैंक का शीशा अचानक टूट गया। टैंक में करीब 20 हजार लीटर पानी भरा था। शीशा टूटते ही पानी और कांच के टुकड़े दर्शकों की तरफ जा गिरे। इस हादसे में चार बच्चों समेत 15 लोग घायल हो गए।

साजिश नाकाम... ट्रेन गुजरते ही हुआ जोरदार धमाका

राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर एक बड़ी और खतरनाक साजिश नाकाम हो गई। यहां उपद्रवियों ने ट्रेन को उड़ाने के लिए ट्रैक पर विस्फोटक रख रखा था, जिसमें जोरदार धमाका हुआ। धमाके से कुछ ही देर पहले एक ट्रेन गुजरी थी। अगर ट्रेन धमाके की चपेट में आती तो सैकड़ों यात्रियों की जान चली जाती। ट्रैक पर रखा विस्फोटक में धमाका इतना जोरदार ता कि यहां सीमेंट के दो भारी ब्लाक टूट गए और पटरियों के बीच 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया।

पाक में 7000 रुपये का गैस सिलेंडर

इस्लामाबाद। ईरान अमेरिका का समझौता कराने कूदे पाकिस्तान में सबसे बड़ा संकट एलपीजी का खड़ा हो गया है, ईरानी बॉर्डर से सप्लाई ठप होने के चलते पाकिस्तान में गैस सिलेंडरों की कीमत 7 हजार रुपए पर जा पहुंची है।

अमेरिकी युद्धपोत होर्मुज में आए तो गोरिल्ला अटैक

तेहरान। ईरान की सेना ने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए ऐलान किया कि यदि अमेरिकी युद्ध पोत होर्मुज में नजर आए तो उन्हें गोरिल्ला मिसाईल अटैक कर समाप्त कर दिया जाएगा। ईरान ने तट के पास ही सुरंगे बना रखी है।

अखिलेश ने किया ऐलान... चुनाव नहीं लड़ूंगा... सीधे सीएम बनूंगा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी की एक सभा में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अखिलेश ने कहा कि यही हमारे लिए शुभ है, इसलिए वही काम करेंगे, जो शुभ होगा। उन्होंने कहा कि हम तब मुख्यमंत्री बनते हैं, जब चुनाव नहीं लड़ते हैं। अखिलेश जब 2012 में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय वह उत्तरप्रदेश विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं थे, बल्कि कन्नौज से सांसद थे। सीएम बनने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था।

खाड़ी में एक और भारतीय की मौत, अब तक 23 लोग मरे

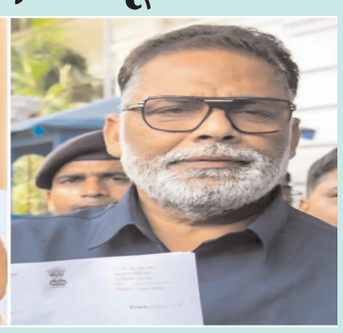
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष में अब तक 23 भारतीयों की मौत हुई है। इनमें से 15 नाविक हैं, जबकि 8 वे लोग हैं, जो खाड़ी देशों में नौकरी करने गए थे। कल होर्मुज में एक और जहाज पर हमला हुआ, जिसमें सवार एक भारतीय गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। विदेश मंत्रालय ने जहाजों पर हो रहे हमलों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी पर विवाद बढ़ा, पप्पू यादव ने की एफआईआर की मांग

पटना. भगवान श्रीकृष्ण को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के स्वरूप की तुलना करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी कुछ भाव-भंगिमाओं को लेकर भी आपत्ति जताई गई। इसके बाद मथुरा-वृंदावन के संतों और कृष्ण भक्तों ने टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की।पप्पू यादव ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस टिप्पणी से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। यादव ने कहा, कानून सभी के लिए समान है, फिर ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनके मुताबिक, पहले धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा था और अब धर्म के भीतर भी विभाजन की कोशिश हो रही है। उन्होंने इस टिप्पणी के पीछे किसी राजनीतिक दल की





भूमिका होने का भी आरोप लगाया।

विवाद बढ़ने पर शास्त्री ने मांगी माफीविवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के बीच किसी तरह का अंतर बताना उनकी मंशा नहीं थी। उनकी टिप्पणी भक्ति परंपरा और ब्रज की प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति के संदर्भ में थी। यदि उनकी बातों से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि भगवान राम और श्रीकृष्ण एक ही परम सत्ता के स्वरूप हैं। वह स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के भक्त हैं और भागवत कथा भी करते हैं। उनका उद्देश्य किसी भी भगवान का अपमान करना या दोनों के बीच भेद करना नहीं था।

रामकथा के दौरान की थी टिप्पणी

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित रामकथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा था कि श्रीराम सीधे हैं, जबकि श्रीकृष्ण तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण की त्रिभंग मुद्रा, बांसुरी और वृंदावन का जिक्र करते हुए अयोध्या और वृंदावन की भी तुलना की थी।

इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मथुरा-वृंदावन के संतों और कृष्ण भक्तों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों समान रूप से पूजनीय हैं और इस तरह उनकी तुलना करना उचित नहीं है। विवाद के बीच केन्या के नैरोबी से जारी वीडियो संदेश में शास्त्री ने अपनी बात का संदर्भ स्पष्ट करते हुए कहा कि भावावेश में कही गई टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए क्षमा मांगते हैं।

देवास टीआई दिलीप पुरी की पत्नी को मिलेगी एसआई पद पर अनुकंपा नियुक्ति, 1 करोड़ की आर्थिक मदद

भोपाल. देवास जिले के खातेगांव में शराब तस्करों के ट्रक की चपेट में आने से टीआई दिलीप पुरी की मौत के बाद से इलाके में शोक छाया हुआ है। उनका परिवार ग्राम बरमंड में रहता है। वहीं पर उनकी जन्म हुआ था। यहीं पर प्राथमिक शिक्षा भी पूरी हुई थी। जिसके बाद हायर सेंकडरी तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की। साल 2007 में पुलिस विभाग में चुने गए। गांव के लोगों को कहना है कि उन्होंने स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का काम भी किया था। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि शहीद टीआई के परिवार को 1 करोड़ व पत्नी को सब इंस्पेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी.जानकारी के लिए बता दें कि शराब माफिआओं को थाना प्रभारी ने गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा, तभी चालक ने आयशर को डिवाइडर पर चढ़ाकर आगे बढ़ा दिया, जिस कारण टीआई की जान चली गई। हादसे की जानकारी मिलते ही एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन में शोक की लहर है। कुछ देर बाद खातेगांव थाने पर



श्रद्धांजलि सभा होगी।टीआई दिलीप पुरी की मौत पर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट करके कहा है कि देवास जिले के खातेगांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कर्तव्य निर्वहन करते हुए थाना प्रभारी श्री दिलीप पुरी जी के दिवंगत होने का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।वीर बलिदानी श्री दिलीप पुरी जी की धर्मपत्नी को एसआई के पद पर अनुकंपा नियुक्ति एवं परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

दोषियों को मिलेगी सजा

इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि, देवास जिले के खातेगांव टीआई श्री दिलीप पुरी, पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, एक अप्रिय हादसे का शिकार होकर दिवंगत हो गए। श्री पुरी ने पूर्ण बहादुरी और समर्पण भाव से पुलिस सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित किया। दुःख की इस घड़ी में हमारी गहरी संवेदनाएं परिवारजन एवं पुलिस परिवार के साथ है। मैंने देवास कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बात की है। घटना के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। मैं आश्वस्त करता हूं कि इस घटना के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इसके प्रत्येक दोषी को सलाखों के पीछे भेजेगी।

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में ट्रंप को झटका, डेमोक्रेट्स को बढ़त, रिपब्लिकन कई सीटों पर पिछड़े

वाशिंगटन. अमेरिका में 3 नवंबर को हुए मिडटर्म चुनाव के शुरुआती नतीजों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को कई सीटों पर पीछे रहना पड़ा है. शुरुआती रुझानों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) और सीनेट, दोनों में बढ़त बनाई है. हालांकि, मतगणना जारी होने के कारण अंतिम नतीजों की तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हुई है.शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, प्रतिनिधि सभा की घोषित सीटों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 127 सीटें जीती थीं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को 74 सीटें मिली थीं. वहीं, सीनेट में डेमोक्रेट्स और उनके सहयोगियों



को 46 सीटें, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को 37 सीटें मिली थीं.

चुनाव से पहले हुए सर्वेक्षणों में भी ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में गिरावट के संकेत मिले थे. रॉयटर्स/इप्सोस के सर्वे के अनुसार, उनकी अप्रूवल रेटिंग 32 फीसदी थी. वहीं, कांग्रेस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को 46 फीसदी और रिपब्लिकन पार्टी को 38 फीसदी मतदाताओं का समर्थन मिलने का अनुमान जताया गया था. महंगाई और बढ़ती जीवनयापन लागत चुनाव के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे.

अमेरिका में राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के मध्य में होने वाले इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 और सीनेट की करीब एक-तिहाई सीटों पर मतदान होता है. इनके नतीजों से तय होगा कि ट्रंप को कार्यकाल के शेष दो वर्षों में संसद का कितना समर्थन मिलेगा. यदि डेमोक्रेट्स किसी एक सदन में भी बहुमत हासिल करते हैं तो सरकार के विधायी एजेंडे और नीतिगत फैसलों पर उनकी निगरानी तथा प्रभाव बढ़ सकता है.

देश के 55 हजार किमी से अधिक हाईवे पर टोल प्लाजा की जगह लगेंगे गेंट्री पोल और सेंसर

नई दिल्ली. देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब पारंपरिक टोल प्लाजा की व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म होने जा रही है. इनके स्थान पर गेंट्री पोल और ओवरहेड सेंसर लगाए जाएंगे. इससे वाहन चालकों को बिना रफ्तार कम किए टोल पार करने की सुविधा मिलेगी और टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी.सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है. नई व्यवस्था के दायरे में 35 हजार किलोमीटर से अधिक निर्माणाधीन और करीब 20 हजार किलोमीटर प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं. इन पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों और फास्टैग स्कैनर की मदद से टोल वसूली की जाएगी. टोल की राशि वाहन चालक के खाते से स्वत- कट जाएगी.दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे- दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत और शामली तथा उत्तराखंड को जोड़ने वाले इस निर्माणाधीन 4/6 लेन एक्सप्रेसवे पर गेंट्री आधारित टोल व्यवस्था तैयार की जा रही है.उत्तर प्रदेश के चार नए लिंक



एक्सप्रेसवे- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल लिंक से जोड़ने वाले नेटवर्क के साथ जेवर एयरपोर्ट, झांसी और फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे पर भी टोल प्लाजा की जगह नई तकनीक अपनाई जाएगी.नई व्यवस्था में %जितना सफर, उतना भुगतान% का सिद्धांत लागू होगा. वाहन चालकों को एकमुश्त टोल देने के बजाय हाईवे पर तय की गई वास्तविक दूरी के आधार पर शुल्क चुकाना होगा. इसके लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित टोलिंग व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का लक्ष्य 2028-29 तक रखा है.

नवीन पटनायक के लापता पोस्टर से ओडिशा में सियासी बवाल, BJP-BJD आमने-सामने

भुवनेश्वर. ओडिशा की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. गंजाम जिले के हिंजिली विधानसभा क्षेत्र में उनके गुमशुदा होने के पोस्टर लगाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. पोस्टर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.जानकारी के मुताबिक, गंजाम जिले के हिंजिली इलाके में नवीन पटनायक की तस्वीर के साथ उन्हें लापता बताते हुए पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू हुई और देखते ही देखते मामला



राजनीतिक विवाद का रूप लेने लगा. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पोस्टर किसने लगाए और इसके पीछे किसका हाथ है. किसी भी व्यक्ति या संगठन ने इसकी जिम्मेदारी सार्वजनिक रूप से नहीं ली है.वीन पटनायक हिंजिली विधानसभा सीट से विधायक हैं. ऐसे में उनके निर्वाचन क्षेत्र में पोस्टर लगाए जाने को चक्रवात के बाद पैदा हुए हालात से जोड़कर देखा जा रहा है. चर्चा है कि प्राकृतिक आपदा के बाद क्षेत्र में राहत और प्रभावित लोगों की स्थिति को लेकर उनकी कथित गैरमौजूदगी पर सवाल उठाने के उद्देश्य से ये पोस्टर लगाए गए हो सकते हैं.गंजाम जिले में चक्रवात और बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ था. राज्य में आई भीषण बाढ़ से करीब 13 लाख लोग प्रभावित होने की जानकारी सामने आई थी. हालांकि, पोस्टर लगाने की वजह और इसके पीछे की मंशा की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. विवाद के बाद सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी बीजेडी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा की ओर से नवीन पटनायक की अपने विधानसभा क्षेत्र में मौजूदगी और जनता के बीच उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं, बीजेडी अपने नेता के बचाव में सामने आई है और उनकी भूमिका को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब दे रही है.

छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के समापन समारोह शामिल हुए

एसआईआर पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार, विपक्ष सदन चलने दे- गृह मंत्री

रायपुर. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के मुद्दे पर विपक्ष को संसद में चर्चा की चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को संसद की कार्यवाही बाधित करने के बजाय सदन चलने देना चाहिए.शाह मंगलवार को छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होने अटल नगर-नवा रायपुर पहुंचे थे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहे. इस दौरान शाह ने राज्य के गठन, विकास, नक्सलवाद के खात्मे और सांस्कृतिक विरासत पर बात रखी.

उन्होंने छत्तीसगढ़ के गठन का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देते हुए कहा कि वर्ष 2000 में राज्य की स्थापना कर उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग पहचान दी. उस समय क्षेत्र का विकास ठहर गया था और इसके साथ अन्याय हो रहा था. शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया गया है. आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ते हुए विकास के नए रास्ते पर अग्रसर है.

नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के योगदान की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत का



लक्ष्य हासिल करने में सुरक्षा बलों की भूमिका अहम है.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि पार्टी ने असंवैधानिक सरकारों और सांसदों का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में निर्वाचित सरकार नहीं थी, वहां नक्सलियों ने अपना गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तक बना रखा था. शाह ने सवाल उठाया कि उन्हें ऐसी व्यवस्था चलाने का अधिकार किस संविधान ने दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलियों ने पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों सहित कई निर्दोष लोगों की हत्या की. राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वे संसद में ऐसी व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं.

शाह ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु घासीदास और गुरु नानक देव के संदेशों में निहित समानता, सेवा और सत्य के मूल्य प्रदेश की परंपरा का हिस्सा हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ पंडुम, बस्तर ओलंपिक, पंथी, पंडवानी, राउत नाचा, करमा और सैला नृत्य जैसी लोक परंपराओं के संरक्षण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की.

उन्होंने ढोकरा कला, बेल मेटल, कास्ट क्राफ्ट और कोसा को छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान बताते हुए कहा कि 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे की अनूठी परंपरा को भी राज्य सरकार ने नई पहचान दी है.

गृह मंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देकर उसकी पहचान स्थापित की थी. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

दीपावली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 11 प्रतिष्ठानों की जांच में 26 नमूने लिए

इंदौर। दीपावली के त्योहार को देखते हुए बाजार में खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शहरभर में जांच अभियान तेज कर दिया है। उपभोक्ताओं को मिलावटरहित एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन और नापतोल विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 11 प्रतिष्ठानों की जांच की गई और खाद्य पदार्थों के 26 नमूने एकत्रित किए गए। दो प्रतिष्ठानों पर नापतोल विभाग ने भी संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अभियान वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में चलाया गया।

छोटा बांगड़दा स्थित मुस्कान डेयरी से पनीर, ट्रेडिशनल स्वीट्स और घी के तीन नमूने लिए गए, जबकि स्कीम नंबर 51 की स्नेहल डेयरी से पनीर एवं घी के दो नमूने संग्रहित किए गए। राधास्वामी नगर स्थित राममोहन दूध-दही भंडार से दूध का नमूना लिया गया। एसडीए कंपाउंड मूसाखेड़ी स्थित श्री बसंत इंटरप्राइजेज से कीर्ति गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया। यहां नापतोल विभाग की जांच में तेल के पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएं और वजन नियमानुसार मिले, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन का सत्यापन नहीं होने पर उसे जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। फार्मर्स मिल्क कार्ट से मावा, मिल्क केक, रसगुल्ला और केसर पेड़ा के नमूने लिए गए।

जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा संबंधी कमियां भी सामने आईं। फार्मर्स मिल्क कार्ट में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर संचालक को सुधार सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। यहां असत्यापित बाट भी नापतोल



विभाग ने जब्त किया। साउथ तुकोगंज स्थित श्रीवारी फूड वेंचर्स से उड़द दाल का नमूना लिया गया। निरीक्षण में कीट नियंत्रण व्यवस्था में कमी और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं पाए गए, जिस पर नोटिस जारी किया जा रहा है। पगनिशपागा स्थित एसएस ट्रेडिंग फर्म से चार प्रकार के खाद्य तेल एवं वनस्पति के नमूने लिए गए, जबकि खातीवाला टैंक स्थित पूजा नमकीन भंडार से मूंगफली तेल, बेसन और सोनपापड़ी के तीन नमूने संग्रहित किए गए।

तेजाजी नगर स्थित नवशक्ति दूध डेयरी एंड स्वीट्स में मावा और पनीर की मैजिक बॉक्स एवं टेस्ट किट से प्रारंभिक जांच की गई। यहां से मावा, पनीर, मावा रोल और पेड़ा के चार नमूने लिए गए। इसी क्षेत्र के श्रीकृष्ण दूध-दही भंडार से मिश्रित दूध तथा खंडवा नाका स्थित सांवरिया दूध डेयरी से गुपचुप और केसर पेड़ा के नमूने संग्रहित किए गए। इसके अलावा खाद्य विभाग की टीम ने उच्च न्यायालय एवं एलआईसी कार्यालय परिसर के आसपास के स्ट्रीट वेंडर्स को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रखरखाव और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। सभी 26 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी। त्योहार तक यह अभियान जारी रहेगा।

दीपावली पर तीन दिन बंद रहेगी इंदौर की मशहूर सराफा चाट चौपाटी, 6 से 8 नवंबर तक नहीं मिलेगा जायका

इंदौर। देशभर में अपने लजीज व्यंजनों के लिए पहचान रखने वाली इंदौर की प्रसिद्ध सराफा चाट चौपाटी दीपावली के अवसर पर तीन दिनों तक बंद रहेगी। इसके चलते 6, 7 और 8 नवंबर को शहरवासी और बाहर से आने वाले पर्यटक यहां के मशहूर व्यंजनों का स्वाद नहीं ले सकेंगे। सराफा चौपाटी एसोसिएशन ने धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। इन तीन दिनों में सराफा बाजार में केवल आभूषणों और सोने-चांदी का कारोबार होगा। दीपोत्सव के दौरान सराफा की दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं और बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंचते हैं।



दरअसल, दीपावली पर सराफा और आसपास के राजवाड़ा क्षेत्र में खरीदारी का सिलसिला देर रात तक चलता है। ऐसे में रात्रिकालीन चाट चौपाटी का संचालन करना संभव नहीं हो पाता। इस बार पूरे बाजार को आकर्षक रोशनी और पारंपरिक सजावट से दुल्हन की तरह सजाया गया है। रास्तों के दोनों ओर वंदनवार लगाए गए हैं और ग्राहकों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है। दीपावली के दौरान सराफा में प्रतिदिन करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। पुष्य नक्षत्र पर भी रात 12 बजे तक ग्राहकों की भीड़ रही। व्यापारियों ने खरीदारी बढ़ाने के लिए आकर्षक उपहार योजनाएं भी शुरू की हैं। 7 नवंबर तक बाजार में रौनक बने रहने की संभावना है।

इंदौर का सराफा बाजार सौ साल से अधिक पुराना है और इसका इतिहास होलकर शासनकाल से जुड़ा हुआ है। उस समय व्यापारियों को सोने-चांदी के कारोबार के लिए यहां स्थान उपलब्ध कराया गया था। बाजार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में होलकर शासकों के सैनिकों के आवास भी बनाए गए थे, ताकि रात के समय भी व्यापारिक गतिविधियों और दुकानों की सुरक्षा बनी रहे। इसी व्यवस्था के बीच रात में खानपान की दुकानें और चाट-पकौड़ों का कारोबार शुरू हुआ, जो आगे चलकर प्रसिद्ध रात्रिकालीन सराफा चौपाटी के रूप में विकसित हुआ। आज यह चौपाटी इंदौर की सांस्कृतिक और खानपान की पहचान बन चुकी है।

धार में सहकारी समिति प्रबंधक के तीन ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, आय से 271 फीसदी अधिक संपत्ति उजागर

इंदौर। धार जिले में लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक शेरसिंह ठाकुर के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की। शुरुआती जांच में उनके पास ज्ञात आय से कहीं अधिक संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त के अनुसार, करीब 20 वर्षों की सेवा अवधि में ठाकुर को वेतन के रूप में लगभग 65 लाख रुपए प्राप्त हुए, जबकि इस दौरान उन्होंने 2 करोड़ 41 लाख 45 हजार रुपए की संपत्ति अर्जित करने और खर्च करने का हिसाब सामने आया है। यह राशि उनकी वैध आय से 271.46 प्रतिशत अधिक बताई गई है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

लोकायुक्त की तीन टीमें सोडपुर, नालछा और मांडव स्थित ठिकानों पर संपत्तियों और



दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। जांच में सोडपुर में 0.1520 हेक्टेयर भूखंड पर 2400 वर्गफीट क्षेत्रफल में निर्मित दो मंजिला मकान की जानकारी मिली है। भूखंड खरीदने और भवन निर्माण पर करीब 97 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा नालछा में मांडव रोड स्थित सोडपुर तिराहे पर 1350 वर्गफीट का व्यावसायिक भवन भी सामने आया है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है। ठाकुर की पत्नी कविता के नाम पर भी कृषि भूमि खरीदे जाने की जानकारी मिली है। सोडपुर में 0.645 हेक्टेयर जमीन आठ लाख रुपए तथा मांडव में 2.526 हेक्टेयर जमीन 42 लाख रुपए में खरीदी गई।

सर्च कार्रवाई के दौरान ठाकुर के पास जेसीबी, महिंद्रा ट्रैक्टर, महिंद्रा टीयूवी, ऑल्टो कार, बुलेट मोटरसाइकिल और विभिन्न कृषि उपकरण भी मिले हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 53 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा उनसे जुड़ी एक अन्य बेनामी संपत्ति के रूप में भवन की जानकारी सामने आई है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. राजेश सहाय के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई में डीएसपी आनंद चौहान सहित निरीक्षक आशुतोष मिठास, प्रतिभा तोमर और सचिन पटेरिया शामिल हैं। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश तथा डीआईजी मनोज सिंह के मार्गदर्शन में जांच जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, दस्तावेजों और संपत्तियों का मूल्यांकन पूरा होने के बाद अनुपातहीन संपत्ति का अंतिम आकलन किया जाएगा।



दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले इंदौर में हड़कंप, तीन निजी स्कूलों और महापौर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी

इंदौर, शहर में आगामी 15 नवंबर को प्रस्तावित पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। शहर के तीन प्रतिष्ठित निजी स्कूलों के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं। इन संदेशों के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संस्थानों और महापौर कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी। धमकी भरे ईमेल की सूचना पर पुलिस की टीमें तत्काल सक्रिय हुईं और सभी प्रभावित स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया।

क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया के मुताबिक, शुरुआती जांच में धमकी भरे ईमेल फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस टीमों ने तीनों स्कूलों और संबंधित परिसरों में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अब तक किसी भी स्थान से संदिग्ध वस्तु अथवा विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। अधिकारियों के अनुसार, स्कूलों को पंजाबी भाषा में ईमेल भेजे गए थे। इनमें विशेष रूप से चेतावनी दी गई थी कि वे अपने विद्यार्थियों को दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए नहीं भेजें। ईमेल में इस्तेमाल की गई भाषा और कार्यक्रम से पहले धमकी मिलने के समय को देखते हुए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है।

तीनों स्कूलों के अलावा महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय को भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। यह संदेश भी दिलजीत दोसांझ के प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की सहायता से ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसके मूल स्रोत का पता लगाया जा रहा है। इसके लिए आईपी एड्रेस सहित तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरे संदेश किसी शरारती तत्व की करतूत हैं या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है। फिलहाल सभी संबंधित स्थानों की सुरक्षा और ईमेल की तकनीकी जांच पर पुलिस की नजर बनी हुई है।

थाना प्रभारी को ट्रक से कुचलने के मामले का मुख्य आरोपी शॉर्ट एनकाउंटर में घायल, एएसआई की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश

देवास। खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी गोस्वामी को ड्यूटी के दौरान ट्रक से कुचलने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी गजेंद्र रावत उर्फ अक्कू का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। घटना राजोदा और बरोठा के बीच की है, जहां एसआईटी की टीम आरोपी को लेकर खातेगांव जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर हिरासत से भागने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सुरक्षा में तैनात एएसआई की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा।

जानकारी के अनुसार, एसआईटी टीम आरोपी गजेंद्र रावत को लेकर खातेगांव की ओर रवाना हुई थी। रास्ते में राजोदा और बरोठा के बीच पुलिस वाहन का टायर अचानक पंचर हो गया। इसके बाद पुलिसकर्मी वाहन रोककर टायर बदलने लगे। इसी दौरान आरोपी ने लघुशंका जाने की इच्छा जताई। सुरक्षा घेरे में मौजूद एएसआई उसे वाहन से कुछ दूरी पर लेकर गए। इसी मौके का फायदा उठाकर गजेंद्र



ने अचानक एएसआई की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और वहां से भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी।

अचानक हुई फायरिंग के बाद एसआईटी की टीम ने मोर्चा संभालते हुए आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। इस दौरान पुलिस की एक गोली गजेंद्र के पैर में लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद टीम ने तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया तथा छीनी गई सर्विस रिवॉल्वर भी बरामद कर ली। घटना के बाद घायल आरोपी को देर रात जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी पर ट्रक चढ़ाने के गंभीर मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे लेकर आगे की जांच और पूछताछ के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में यह घटनाक्रम सामने आया।

स्व-सहायता समूह की दीदियों के उत्पादों की बिक्री-सह-प्रदर्शनी आयोजित

ग्रामीण स्वावलंबन की रोशनी से जगमगाएगी दीपावली - शिवम वर्मा कलेक्टर इंदौर

राकेश चन्दन। सिटी चीफ

इंदौर, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके कौशल को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदौर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जिला पंचायत इंदौर) द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा निर्मित दीपावली सामग्री की बिक्री-सह-प्रदर्शनी आयोजित की गई है।

प्रदर्शनी में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने हुनर, मेहनत एवं रचनात्मकता से तैयार किए गए आकर्षक दीप, दीये, सजावटी सामग्री एवं दीपावली से संबंधित विभिन्न हस्तनिर्मित उत्पाद बिक्री हेतु प्रदर्शित किए गए हैं।

इस अवसर पर कलेक्टर महोदय द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया तथा स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा



तैयार किए गए उत्पादों की सराहना की गई। उन्होंने महिलाओं से उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया एवं उनके व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की।

कलेक्टर महोदय ने महिलाओं के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम हैं। स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहन एवं बाजार उपलब्ध कराने से महिलाओं की आय में वृद्धि होगी तथा वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।

आजीविका मिशन का यह प्रयास ग्रामीण महिलाओं के हुनर को पहचान दिलाने के साथ-साथ वोकल फॉर लोकल एवं महिला स्वावलंबन की भावना को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

जिला पंचायत इंदौर द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि इस दीपावली पर स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर उनके आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों में सहभागी बनें और उनकी दीपावली को खुशियों से रोशन करें।

आदिवासी युवाओं के प्रदर्शन मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मेधावी छात्र के खिलाफ FIR और आरोप पत्र निरस्त

इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने आदिवासी युवाओं के समर्थन में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता राजेश अचालिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर, आरोप पत्र और निचली अदालत के संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अपराध में संबंधित लोक सेवक अथवा उसके वरिष्ठ अधिकारी की लिखित शिकायत के बिना न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता। अदालत ने यह भी कहा कि एक मेधावी छात्र का भविष्य केवल इसलिए आपराधिक मुकदमे में उलझाकर प्रभावित नहीं किया जा सकता कि वह आदिवासी समुदाय के लोगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था।



मामला बड़वानी जिले के पलसूद थाने का है। पुलिस ने 30 जून 2024 को आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके विरोध में जय आदिवासी युवा शक्ति के सात कार्यकर्ताओं ने 6 जुलाई 2024 को पलसूद थाने पहुंचकर प्राथमिकी निरस्त करने की मांग करते हुए नारेबाजी की थी। पुलिस ने प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं लेने और जिला दंडाधिकारी के धारा 144 के तहत जारी आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बीएनएस की धारा 223 में प्रकरण दर्ज किया। बाद में आरोप पत्र में धारा 126(2) भी जोड़ दी गई और पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। निचली अदालत ने 16 दिसंबर 2024 को मामले में संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पर्व बिरला ने दलील दी कि बीएनएसएस की धारा 215 के तहत संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत अनिवार्य थी, जो इस मामले में मौजूद नहीं थी।

हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि लिखित शिकायत की अनिवार्यता से बचने के लिए एक ही घटना से जुड़े अपराधों को अलग-अलग करके कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के देवेंद्र कुमार मामले का भी उल्लेख किया। घटनास्थल के नक्शे और जांच दस्तावेजों के परीक्षण में प्रदर्शनकारियों के थाना भवन से कुछ दूरी पर खड़े होने की बात सामने आई, जिससे शासकीय कार्य में बाधा के आरोप पर भी सवाल उठे। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि उसने 12वीं में पांच में से चार विषयों और 10वीं में दो विषयों में विशेष योग्यता हासिल की है। वह डीएलएड पूरा करने के साथ प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुका है। अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार कर एफआईआर, आरोप पत्र और संज्ञान आदेश निरस्त कर दिए।



संघ के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी, 46 प्रांतों की जगह बन सकते हैं 85 से 90 संभाग

इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने लगातार बढ़ते कार्यक्षेत्र और संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए देशभर में प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित बदलाव के तहत वर्तमान प्रांत व्यवस्था समाप्त कर संभागीय संरचना लागू की जा सकती है। इसके साथ ही देश में मौजूदा 922 जिलों की संख्या बढ़ाकर लगभग दोगुनी करने पर भी मंथन चल रहा है। वर्तमान में संघ के 11 क्षेत्र हैं, जिन्हें घटाकर नौ करने का प्रस्ताव है। वहीं, 46 प्रांतों के स्थान पर 85 से 90 संभाग बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य प्रचारक और राज्य कार्यालय की व्यवस्था शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। संघ का मानना है कि छोटे कार्यक्षेत्र से पदाधिकारियों की सक्रियता और संगठनात्मक निर्णयों की गति बढ़ेगी।इंदौर के डेली कॉलेज में आयोजित संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को संगठनात्मक पुनर्गठन के इन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।

अब हर टोल प्लाजा की भोपाल मुख्यालय से होगी रियल टाइम निगरानी

प्रदेश के 149 टोल प्लाजा को एक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी; पहली बार नेटवर्क, कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफर की गड़बड़ी पर नजर

भोपाल, मध्य प्रदेश में टोल प्लाजा के संचालन और नेटवर्क व्यवस्था की निगरानी अब भोपाल मुख्यालय से करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) प्रदेश के 149 टोल प्लाजा को एक सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने जा रहा है। खास बात यह है कि जुलाई में 3.81 करोड़ रुपये की लागत से जारी टेंडर पर कोई ठेकेदार नहीं मिला। इसके बाद निगम ने की बढ़ोतरी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा पर नेटवर्क डाउन होने, कनेक्टिविटी बाधित होने, डेटा ट्रांसफर में गड़बड़ी या बैंडविड्थ कम मिलने जैसी समस्याओं की तकनीकी खराबी का पता लगाने और उसे दूर करने में लगने वाला समय कम करने का लक्ष्य है। साथ ही टोल संचालन और राजस्व संग्रह से जुड़े आंकड़ों का केंद्रीकृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

भोपाल से उज्जैन तक 11 डिवीजन के टोल जुड़ेंगे

एमपीआरडीसी की योजना में प्रदेश के 11 डिवीजन के 149 टोल प्लाजा शामिल हैं। इनमें भोपाल डिवीजन के 20, ग्वालियर के 19, छिंदवाड़ा के आठ, धार के 20, इंदौर के नौ, जबलपुर के 10, नर्मदापुरम के तीन, रीवा के 13, सागर के 15, शहडोल के नौ और उज्जैन के 23 टोल प्लाजा शामिल हैं। डिजिटल नेटवर्क तैयार होने के बाद प्रदेशभर के टोल प्लाजा की तकनीकी निगरानी भोपाल मुख्यालय से करने का रास्ता खुलेगा। अब इस परियोजना की अगली चुनौती संशोधित लागत पर ठेकेदार तय करना और नेटवर्क को निर्धारित समय में चालू करना होगी।

टेंडर में प्रतिस्पर्धा नहीं, अब बढ़ी लागत

एमपीआरडीसी ने प्रदेश के टोल प्लाजा को मैनेज्ड मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया जुलाई में शुरू की थी। इसके लिए 3.81 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया, लेकिन इस राशि पर कोई ठेकेदार नहीं मिला। ऐसे में निगम ने लागत का पुनर्मूल्यांकन किया और परियोजना के बजट में 20 लाख रुपये बढ़ा दिए। अब परियोजना की संशोधित लागत करीब 4.01 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि, लागत बढ़ने के बाद टेंडर की आगे की प्रक्रिया और काम पूरा होने की समय-सीमा के बारे में जानकारी सामने आना बाकी है।

हर टोल का नेटवर्क स्टेटस भोपाल से दिखेगा

परियोजना के तहत प्रत्येक टोल प्लाजा को समर्पित एमपीएलएस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। भोपाल स्थित एमपीआरडीसी मुख्यालय को हाई-स्पीड नेटवर्क हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यालय से टोल प्लाजा की कनेक्टिविटी, नेटवर्क उपलब्धता और डेटा ट्रैफिक की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। यदि किसी टोल पर नेटवर्क बाधित होता है या डेटा ट्रांसमिशन में समस्या आती है, तो कंट्रोल सेंटर को इसकी सूचना मिल सकेगी। इससे तकनीकी गड़बड़ी की पहचान के लिए मौके से शिकायत आने का इंतजार करने की जरूरत कम होगी। नेटवर्क व्यवस्था दुरुस्त रहने से टोल संचालन में बाधा घटाने और निगरानी को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की बनाए रखना नहीं, बल्कि टोल संचालन से जुड़े आंकड़ों को एक जगह दर्ज करना भी है। केंद्रीकृत रिकॉर्ड से परिचालन की समीक्षा, राजस्व प्रबंधन और भविष्य की योजना तैयार करने में सुविधा होगी।

तीन दिन में चेहरा पंजीयन नहीं कराया तो रुक जाएगा वेतन



भोपाल, मंत्रालय सहित सतपुड़ा और विंध्याचल भवनों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति अब रजिस्टर में नहीं चेहरे से ऑनलाइन दर्ज होगी। नई हाजिरी व्यवस्था को लागू करने प्रशासन ने सभी को स्वयं पंजीयन के लिये तीन दिन का समय दिया है। इसके बाद करीब 3 हजार अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके लिये विभागों को सख्त निर्देश जारी किये गये हैं। इसके पहले 9 अक्टूबर को भी स्वयं पंजीयन के संबंध में पत्र जारी किया था, लेकिन फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम (एफआरएएस) के क्रियांवयन में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसको देखते हुए अब 6 नवंबर तक पंजीयन पूरा करने की अंतिम समयसीमा तय कर दी गई है। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में पंजीयन नहीं कराने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का आगामी माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।

मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर होगा पंजीयनः पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। कर्मचारी अपने मोबाइल से आधिकारिक लिंक या क्यूआर कोड स्कैन कर यह कर सकेंगे। तकनीकी परेशानी आने पर विभाग के पीईएमटी विशेषज्ञ की मदद भी दी गई है। इसके अलावा तीनों भवनों के मुख्य प्रवेश द्वारों पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं।

एनएसओ की लेबर मार्केट स्नैपशॉट ऑफ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट में खुलासा

भोपाल में हर 10 में करीब 3 युवा निठल्ले

भोपाल, राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में युवाओं को शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए योजनाएं तो कई हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में युवा अब भी इन तीनों से बाहर हैं। भोपाल जिले में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 29.2 प्रतिशत युवा न पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं। यानी हर 100 में करीब 29 युवा निठल्ले वाली स्थिति में हैं। यह अनुपात प्रदेश के औसत 22 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत अंक अधिक है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की सितंबर 2026 में जारी लेबर मार्केट स्नैपशॉट ऑफ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट के ये आंकड़े राजधानी में युवाओं को अवसरों से जोड़ने की चुनौती सामने रखते हैं। प्रदेश के दस सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में इस मामले में भोपाल दूसरे स्थान पर है। ग्वालियर में यह अनुपात 29.3 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक है, जबकि जबलपुर में सबसे कम 16.5 प्रतिशत युवा शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण से बाहर हैं। भोपाल और जबलपुर के बीच 12.7 प्रतिशत अंक का अंतर है।

कामकाजी आबादी में भी भोपाल पीछे

भोपाल की तस्वीर केवल युवाओं तक सीमित नहीं है। जिले में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी में महज 48.1 प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, जबकि प्रदेश का औसत 64.1 प्रतिशत है। इस पैमाने पर भोपाल राज्य के औसत से 16 प्रतिशत अंक पीछे है। जिले की बेरोजगारी दर 3.9 प्रतिशत है, जो रिपोर्ट में शामिल दस बड़े जिलों की उपलब्ध दरों में सबसे अधिक है। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि राजधानी में शिक्षा और रोजगार के अवसरों को युवाओं तक पहुंचाने के साथ ही कौशल प्रशिक्षण को वास्तविक रोजगार से जोड़ने की जरूरत है।

तीन साल का रिपोर्ट कार्ड तय करेगा मंत्रियों-विधायकों का सियासी भविष्य

21-22 दिसंबर के चिंतन शिविर में सरकार और संगठन करेंगे कामकाज का आकलन; कमजोर प्रदर्शन वालों पर गिरेगी गाज, कुछ नए चेहरों को मिल सकता है मौका

भोपाल, मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के तीन साल दिसंबर में पूरे होने जा रहे हैं। इस पड़ाव पर सरकार और संगठन के स्तर पर मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के कामकाज का हिसाब-किताब तैयार करने की तैयारी है। 21 और 22 दिसंबर को प्रस्तावित चिंतन शिविर में सरकार के तीन साल के कामकाज पर मंथन होगा। इसी दौरान जनप्रतिनिधियों की परफॉर्मेंस के आधार पर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी अहम संकेत मिल सकते हैं। कमजोर प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सूची तैयार होने और मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावनाओं ने सियासी हलचल बढ़ा दी है।चिंतन शिविर इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भाजपा सरकार के सामने अब केवल योजनाओं और घोषणाओं का लेखा-जोखा पेश करने की चुनौती नहीं है, बल्कि उनके क्रियान्वयन, जनता तक लाभ पहुंचने और संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भी सवाल है। सरकार के तीन साल पूरे होने के साथ यह आकलन किया जा सकता है कि किस जनप्रतिनिधि ने अपने क्षेत्र में सक्रियता दिखाई, किसने सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया और किसकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई है। हालांकि, अभी तक किसी मंत्री को हटाने, विभाग बदलने या किसी विधायक को नई जिम्मेदारी देने का आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है।

सरकार और संगठन के तराजू पर तौले जाएंगे जनप्रतिनिधि

मंत्रियों और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की कवायद में सरकार के कामकाज के साथ संगठन की प्रतिक्रिया भी अहम हो सकती है। किसी मंत्री का विभागीय प्रदर्शन, योजनाओं की प्रगति, जनता से संवाद और क्षेत्र में उसकी उपलब्धता जैसे पहलुओं पर नजर रखी जा सकती है। वहीं विधायकों के मामले में क्षेत्रीय सक्रियता, कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल, जनसमस्याओं के निराकरण और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की क्षमता महत्वपूर्ण हो सकती है। भाजपा की राजनीति में संगठन और सरकार के बीच समन्वय को हमेशा अहम माना जाता रहा है।

मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें तेज

चिंतन शिविर से पहले मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावनाओं ने भी चर्चा को हवा दी है। माना जा रहा है कि यदि सरकार विभागीय प्रदर्शन में अंतर पाती है, तो कुछ मंत्रियों के दायित्व बदले जा सकते हैं। किसी विभाग में कामकाज तेज करने के लिए जिम्मेदारी का पुनर्वितरण भी विकल्प हो सकता है। ऐसे किसी बदलाव का उद्देश्य केवल कमजोर प्रदर्शन करने वालों को हटाना नहीं, बल्कि उन चेहरों को आगे लाना भी हो सकता है, जिनमें अधिक जिम्मेदारी संभालने की क्षमता योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक समन्वय के आधार पर मंत्रिमंडल में बदलाव का फैसला लिया जा सकता है।

कमजोर प्रदर्शन करने वाले विधायकों की बढ़ेगी मुश्किल

समीक्षा में कमजोर प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सूची तैयार किए जाने की चर्चा है। यदि संगठन और सरकार के आकलन में किसी विधायक का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी राजनीतिक भूमिका पर असर पड़ सकता है। ऐसे विधायकों को संगठनात्मक जिम्मेदारी में बदलाव, क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने या आगामी चुनावों से पहले अपनी स्थिति सुधारने का संकेत दिया जा सकता है। भाजपा के लिए यह समीक्षा इसलिए भी अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2028 में होने हैं। चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन का आकलन पार्टी को कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने और सुधार के लिए पर्याप्त समय दे सकता है। यदि किसी विधायक के क्षेत्र में जनता की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की शिकायतें या विकास कार्यों को लेकर असंतोष सामने आता है, तो संगठन समय रहते हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि, रिपोर्ट कार्ड में कमजोर प्रदर्शन सामने आने का मतलब सीधे टिकट कटना नहीं होगा। अंतिम निर्णय लेते समय चुनावी समीकरण, स्थानीय सामाजिक संतुलन, संगठन में स्वीकार्यता और क्षेत्रीय परिस्थितियों जैसे पहलू भी महत्वपूर्ण रहेंगे।

आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का 'प्लस-60' प्लान

भोपाल, मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत कांग्रेस ने आदिवासी राजनीति का दायरा बढ़ाने की रणनीति बनाई है। पार्टी की नजर अब अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन 60 अतिरिक्त सीटों पर भी है, जहां आदिवासी आबादी चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कांग्रेस इस रणनीति को 'प्लस-60' प्लान के तौर पर आगे बढ़ा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को इस पहल के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का जोर इन सीटों पर आदिवासी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी, स्थानीय मुद्दों और दूसरे सामाजिक वर्गों के समीकरणों का अलग-अलग आकलन करने पर है।

कांग्रेस की योजना के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक जैसी रणनीति अपनाने के बजाय प्रत्येक सीट की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर अलग कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसमें आदिवासी आबादी के अनुपात के साथ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय की भागीदारी, पिछले चुनावों में जीत-हार के अंतर तथा स्थानीय किया जाएगा। पार्टी का प्रयास है कि चुनाव से पहले इन क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियों का विस्तृत डाटा तैयार हो, ताकि संगठन और राजनीतिक गतिविधियों की दिशा तय की जा सके।

5 नवंबर को वेतन के लिए होगा प्रदर्शन

भोपाल। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में 175 मृतक कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के महेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया है कि विभाग स्थाई कैडर नहीं होने का हवाला देकर नियुक्तियां टाल रहा है। संघ ने मांग की है कि इन परिवारों को जल्द नियुक्ति दी जाए। वहीं, जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के विरोध में 5 नवंबर को आयुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। शर्मा ने चेतावनी दी कि वेतन भुगतान नहीं होने पर प्रदेश के सभी जिलों में सहायक आयुक्त कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा।

श्रीमती उर्मिला तिवारी स्मृति प्रेरणा सप्तपर्णी सम्मान



भोपाल, पत्रिका 'प्रेरणा समकालीन लेखन के लिए' के सम्पादक अरुण तिवारी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती उर्मिला तिवारी की स्मृति में 'श्रीमती उर्मिला तिवारी स्मृति प्रेरणा सप्तपर्णी सम्मान' के अन्तर्गत 5100/- रूपये की सम्मान राशि एवं प्रशस्तिपत्र दिए जाते हैं। यह सम्मान प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से उनके द्वारा आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2026 का साहित्यिक पत्रकारिता के लिए रवीन्द्र व्यास, लोक भाषा/लोक साहित्य के लिए महेश जोशी, अनुवाद के लिए मीनाक्षी जोशी, साहित्य को समर्पित रुपांकन के लिये अवधेश वाजपेयी को उक्त सम्मान भव्य कार्यक्रम में दिया गया जिसके अध्यक्ष सुप्रसिद्ध नाटककार, कथाकार, सम्पादक, फिल्म स्क्रिप्ट लेखक डॉ असगर वजाहत, दिल्ली, मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध कथाकार डॉ मधु कांकरिया, कोलकाता, उपस्थिति प्रसिद्ध कथाकार, सम्पादक डॉ राजेन्द्र दानी जबलपुर रहे। अरुण तिवारी ने समस्त सम्मानितों को बधाई दी एवं मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भोपाल एवं प्रदेश से आये हुए साहित्यकार उपस्थित थे।

भाजपा सोशल मीडिया विभाग में मनोज सिंह राजपूत को जिम्मेदारी

भोपाल। भाजपा भोपाल नगर के सोशल मीडिया विभाग में मनोज सिंह राजपूत को सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति राजपूत ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जिला अध्यक्ष रविंद्र यती जताते हुए कहा कि संगठन की विचारधारा और जनकल्याणकारी कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

शीतकालीन सत्र में पंचायत कानून बदलने की तैयारी

द्वितीय अनुपूरक बजट भी होगा पेश, कॉलोनाइजर एक्ट का प्रारूप तैयार, मंजूरी मिली तो वह भी एजेंडे में

भोपाल, मध्य प्रदेश में पंचायतों के अधिकारों और विकास कार्यों की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। राज्य सरकार आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पंचायतराज अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक ला सकती है। इसके जरिए ग्रामसभा के अधिकार पंचायत समितियों को देने का प्रस्ताव है। यदि ऐसा होता है तो गांवों में निर्णय लेने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। हालांकि, संशोधन का अंतिम स्वरूप विधेयक और उसके प्रावधान सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह का समय प्रस्तावित किया है। सत्र दिसंबर के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से चर्चा और अनुमोदन के बाद सत्र की अवधि को अंतिम रूप देंगे।

पंचायतों की व्यवस्था में बदलाव पर नजर

सत्र में पंचायतराज अधिनियम संशोधन का मुद्दा अहम रहेगा। प्रस्तावित बदलाव में ग्रामसभा के अधिकार पंचायत समितियों को देने की बात है। यह विषय गांवों में विकास कार्यों, निर्णय प्रक्रिया हालांकि, किन अधिकारों का हस्तांतरण होगा और इसके लिए कौन-से प्रावधान बदले जाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट

सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। इसके माध्यम से निर्माण से जुड़े विभागों को पूंजीगत कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की तैयारी है। ऐसे में सत्र के दौरान विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान और सरकार की प्राथमिकताओं पर भी नजर रहेगी।

ई-विधान से बदलेगा सदन का कामकाज

शीतकालीन सत्र से विधानसभा में ई-विधान व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी है। इसके तहत विधायक प्रश्न-उत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कार्यसूची और अन्य विधायी दस्तावेज डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। विधायकों को 28 से 30 अक्टूबर तक इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विधानसभा का स्थापना दिवस 17 दिसंबर को होता है। पिछले वर्ष इस अवसर पर एक दिवसीय विशेष बैठक आयोजित की गई थी। इस बार सत्र की तारीखों और अवधि को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि सरकार किन विधेयकों को सदन में प्राथमिकता देती है।

टीएनसीपी की पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह पर लोकायुक्त का केस, आय से 250 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप

भोपाल में मकान, कॉम्प्लेक्स से लेकर फार्म हाउस और पेट्रोल पंप तक जांच के दायरे में

भोपाल, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएनसीपी) की पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह लोकायुक्त की जांच के घेरे में आ गई हैं। लोकायुक्त संगठन ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में अपराध दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में उनकी ज्ञात वैध आय की तुलना में करीब 250 प्रतिशत अधिक चल-अचल संपत्ति अर्जित किए जाने की बात सामने आई है। जांच में भोपाल में कई मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फार्म हाउस और पेट्रोल पंप जैसी संपत्तियों का पता चलने का दावा किया गया है।

लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर 3 नवंबर 2026 को यह कार्रवाई की गई। उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त संगठन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है।



परिजनों के नाम पर भी संपत्तियां अर्जित करने का आरोपः लोकायुक्त की प्रारंभिक जांच के अनुसार, सुनीता सिंह ने अपने सेवाकाल के दौरान अपनी वैध आय के अनुपात में करीब 250 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की। शिकायत में आरोप है कि संपत्तियां केवल उनके नाम पर ही नहीं, बल्कि परिजनों के नाम पर भी खरीदी गईं। जांच में भोपाल शहर में स्थित मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फार्म हाउस और पेट्रोल पंप जैसी संपत्तियां सामने आई हैं। हालांकि, अभी इन संपत्तियों के वास्तविक मूल्य, खरीद के स्रोत और उनमें निवेश की गई राशि का विस्तृत आकलन किया जाना बाकी है। लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू की है।अब संपत्तियों के स्रोत खंगालेगा लोकायुक्त

मामला दर्ज होने के बाद अब लोकायुक्त की जांच का मुख्य केंद्र सुनीता सिंह और उनके परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियां होंगी। जांच एजेंसी संपत्तियों की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज, रजिस्ट्री, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की जानकारी जुटाएगी। इसके साथ ही सेवाकाल के दौरान प्राप्त वेतन, अन्य वैध आय और निवेश का भी मिलान किया जाएगा। यह पता लगाया जाएगा कि संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल की गई रकम ज्ञात आय के स्रोतों से मेल खाती है या नहीं। जांच में संपत्तियों के वास्तविक बाजार मूल्य और उनके अर्जन की समयावधि का भी परीक्षण होगा। लोकायुक्त की विवेचना पूरी होने के बाद ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में वास्तविक वित्तीय अंतर और अन्य जिम्मेदारियों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मामला दर्ज हुआ है, आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होना बाकी है।

आज से प्रदेशभर के नगरीय निकायों में सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल



भोपाल, वेतन वृद्धि और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर सफाईकर्मियों ने अब प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मंगलवार, 4 नवंबर से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सफाईकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इससे शहरों की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। भोपाल में सोमवार को दिनभर धरने के बाद भी जब मांगों का ज्ञापन लेने कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा तो कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जहांगीराबाद चौराहे पर करीब दो घंटे तक चक्काजाम किया और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की रणनीति बनाई।अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन (7262) के बैनर तले कर्मचारियों ने सोमवार सुबह 9 बजे शाहजहांनी पार्क में धरना शुरू किया था। उन्होंने सरकार को मांगों पर निर्णय लेने के लिए शाम 4 बजे तक का समय दिया था। कर्मचारी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन निर्धारित समय तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करने का फैसला किया।बैरिकेडिंग हटाकर चौराहे पर पहुंचे कर्मचारीः प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने शाहजहांनी पार्क से निकलने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की थी। कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग हटाई और तलैया थाने के सामने से होते हुए जहांगीराबाद चौराहे पहुंच गए। यहां पुलिस ने दोनों ओर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद कर्मचारी सड़क पर ही बैठ गए और चक्काजाम कर दिया। करीब दो घंटे तक चले प्रदर्शन से पुराने शहर के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने भी वाहनों की आवाजाही बाधित रही। पुलिस को कई रास्तों पर यातायात डायवर्ट करना पड़ा।वेतन बढ़ाने और स्थायी करने की मांगयूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मगनलाल झांझोट ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वेतन वृद्धि, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना और लंबित मांगों का निराकरण शामिल है। लंबे समय से आंदोलन करने के बावजूद मांगों का स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

संपादकीय

घुसपैठिए मतदाता

दिल्ली में विपक्ष की रैली के ठीक अगले दिन हैदराबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं और विशेष रूप से राहुल गांधी को जिस तरह निशाने पर लिया, उससे यह साफ है कि सत्तापक्ष उनके दुष्प्रचार आधारित दबाव में आने के बजाय उनके झूठे नैरेटिव का प्रतिकार करने को प्रतिबद्ध है। मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण की प्रक्रिया यानी एसआइआर के तहत जारी मसौदा सूची से करीब 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाने को विपक्ष केवल वोट चोरी बताने में ही नहीं लगा, बल्कि इस मामले में वकील संग जज भी बना हुआ है।वह यह सुनने-समझने को तैयार नहीं कि इन 13 करोड़ लोगों में 6.30 करोड़ वे हैं, जो स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो गए, करीब 2.80 करोड़ वे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, एक करोड़ से अधिक के नाम दो या तीन जगह दर्ज थे और लगभग तीन करोड़ लोग सत्यापन के समय अपने पते पर मिले ही नहीं। गृहमंत्री ने दो टूक कहा कि ये तीन करोड़ वस्तुतः घुसपैठिए हैं और इनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर होकर रहेंगे। उनका यह दावा इसलिए सच जान पड़ता है, क्योंकि ऐसे तीन करोड़ लोगों के बारे में उनके पड़ोसी भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।आखिर विपक्ष इस पर क्यों तुला है कि जो अन्यत्र बस गए या मर गए अथवा जिनके नाम एक से अधिक जगह दर्ज हैं और जो खोजने पर भी नहीं मिल रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में क्यों होना चाहिए? वह इस सच से अनजान नहीं कि देश में दशकों से बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है और उन्होंने बंगाल, असम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में डेमोग्राफी भी बदल दी है। कांग्रेस, वामदल और तृणमूल कांग्रेस तो यह कहीं अच्छे से जानते हैं कि असंख्य बांग्लादेशियों ने छल-छद्म से हर तरह के पहचान पत्र प्राप्त कर खुद को भारतीय नागरिक में तब्दील कर लिया है, क्योंकि इन दलों ने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उन्हें संरक्षण देकर अपना वोट बैंक बनाया।इसी कारण बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अवैध बांग्लादेशी उत्तर, पश्चिम के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी मतदाता बन गए हैं। विपक्ष ने बिहार में एसआइआर के तहत 65 लाख नाम हटाए जाने पर भी वोट चोरी का शोर मचाया था, लेकिन वह ऐसे 65 लोगों को भी सामने नहीं ला पाया था। तथ्य यह भी है कि कांग्रेस नेता कर्नाटक और केरलम में एसआइआर की प्रक्रिया को सही बताकर चुनाव आयोग को धन्यवाद दे चुके हैं। निःसंदेह यह संभव है कि किसी वैध मतदाता का नाम किसी गलती-गफलत से वोटर लिस्ट से बाहर हो गया हो, पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसका नाम फिर से शामिल हो ही नहीं सकता। आखिर जब इसकी सुविधा उपलब्ध है, तब फिर वोट चोरी के विपक्ष के राग को बेसुरा और बरगलाने वाला ही कहा जाएगा।

प्रदूषण और पटाखे

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उन्हें चलाने की सीमित छूट देने के 24 घंटे बाद यह सामने आया कि राजधानी में पारंपरिक पटाखों की भी खुलेआम बिक्री हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार को उसके निर्देश का पालन करने को कहा। देखना है कि ऐसा हो पाता है या नहीं, क्योंकि बीते वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्देशों के बाद भी पटाखा बेचने वाले उनकी येन-केन-प्रकारेण बिक्री कर ही लेते हैं।वे हरित पटाखों के नाम पर पारंपरिक यानी कहीं अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की भी बिक्री करते हैं। इसका कारण यह है कि इसके ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं कि सभी पटाखे हरित ही हों। आम तौर पर लोग दीवाली पर तय समयसीमा की अनदेखी कर देर रात तक पटाखे छोड़ते रहते हैं। यद्यपि हर कोई इससे परिचित है कि पटाखे प्रदूषण बढ़ाते हैं और पिछले कुछ वर्षों में तो दीवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के अन्य इलाकों में हवा इतनी विषाक्त हो जाती है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है।बहुत कम लोग हैं, जो पटाखों के इस्तेमाल में संयम दिखाते हैं और केवल हरित पटाखे ही चलाते हैं। यह सही है दीवाली पर पटाखों का इस्तेमाल न जाने कब से होता आ रहा है और वे इस पर्व का एक हिस्सा बन गए हैं, लेकिन उनका उपयोग सीमित करके भी तो उल्लासित हुआ जा सकता है। इसके लिए लोग अपनी गली, मोहल्ले में सामूहिक रूप से किसी खुले स्थान पर पटाखे चला सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हरित पटाखे ही चलाए जाएं। इसमें ही सबका हित है।बीते दो-तीन दशक में हालात बदल चुके हैं। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में सर्दियों के आगमन के साथ ही सिर उठाने वाला वायु प्रदूषण दीवाली बाद यकायक बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में सभी को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। समस्या यह है कि औसत लोग जैसे इसकी परवाह नहीं करते कि पुराने वाहन चलाने, पराली अथवा कूड़ा-करकट जलाने, धूल उड़ाने वाला निर्माण कार्य कराने से प्रदूषण बढ़ता है, वैसे ही मनचाहे तरीके से पटाखे चलाने से सांसों के लिए संकट पैदा होता है।इससे भी बड़ी समस्या यह है कि सरकार का प्रदूषण रोधी तंत्र भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी सही तरह निभाने के बजाय खानापूरी ही अधिक करता है। वह तब चेतता है, जब प्रदूषण गंभीर रूप ले लेता है। यह समझा जाए कि सेहत के लिए घातक संकट पैदा करने वाले प्रदूषण से तभी निपटा जा सकता है, जब सरकारी तंत्र के साथ आम जनता भी उसकी रोकथाम के उपायों पर सही से अमल करने को लेकर सजग रहे। यह सजगता दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के शासन-प्रशासन और लोगों को भी दिखानी होगी।

उम्मीदवारों के चयन में हो मतदाताओं की भूमिका

देश का उच्च सदन राज्य सभा हो या राज्यों का उच्च सदन विधान परिषद हो, इसमें सामान्य तौर पर राजनीतिक गुणा गणित में सटीक बैठने वाले व्यक्ति ही आ पाते हैं।ऐसे में संविधान की यह मंशा पूरी नहीं होती है कि उच्च सदन में अनुभवी और विषय विशेष की गहरी जानकारी रखने वाले लोग उच्च सदन में आएंगे और कानून बनाने की प्रक्रिया में योगदान देंगे। इसकी प्रमुख वजह राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल खुद लोकतांत्रिक नहीं हैं।ऐसे में टिकट देने की प्रक्रिया भी अलोकतांत्रिक है। हर राजनीतिक दल में एक दो लोग मिल कर तय करते हैं कि टिकट किसे दिया जाएगा। बड़ी संख्या में सांसदों और विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, इसके बावजूद राजनीतिक दल उनको बेहिचक टिकट देते हैं। जब तक टिकट देने की मौजूदा प्रक्रिया जारी है, ऐसे ही जनप्रतिनिधि सदन में आएंगे, जिनको लोकतंत्र और जनता से कोई मतलब नहीं है।वे पांच वर्ष बस तक अपनी आर्थिक तरक्की और राजनीतिक करियर के लिए काम करते हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि अगली बार भी उनको टिकट मिल जाए।जनता के पास खास विकल्प नहीं है क्योंकि सभी राजनीतिक दलों में टिकट देने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। जनता एक तरह से लाचार है क्योंकि उनके क्षेत्र से चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों में उम्मीदवारों के चयन में जनता की भूमिका होती है।अमेरिका में राजनीतिक दल या शीर्ष नेता यह तय नहीं करते हैं कि चुनाव कौन लड़ेगा, यह फैसला प्राथमिक चुनावों के जरिये जनता करती है। इसी तरह से ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में उम्मीदवारों के चयन में पार्टी के सदस्यों और पार्टी के कैडर की प्रभावी भूमिका होती है। भारत में इस सिस्टम को अपनाया जाना चाहिए।इससे देश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा और चुनाव में धनबल का प्रभाव भी कम होगा। देश में राजनीति ज्यादा समावेशी होगी और अपेक्षाकृत ज्यादा योग्य और साफ सुधरी छवि के लोग संसद और विधानसभाओं में आएंगे।

सबक सिखाने वाले चुनाव

सबसे दिलचस्प चुनाव परिणाम सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आए। यहां 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा छह, जबकि सपा पांच सीटें जीतने में सफल रही। यह आंकड़ा भाजपा की बढ़त तो बताता है, लेकिन विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले सपा का ऐसा प्रदर्शन सत्तारूढ़ दल के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए भी कि सपा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटें जीतने में सफल रही। सपा लखनऊ और आगरा की सीट भी जीत गई। इससे यह संकेत भी मिलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद भाजपा जरूरी सुधारात्मक कदम नहीं उठा पाई है।

चार राज्यों में शिक्षक एवं स्नातक वर्ग की 28 विधान परिषद सीटों के चुनाव परिणाम फिर याद दिलाते हैं कि 'व्यवस्था' में 'तंत्र' भले 'लोक' पर हावी हो गया हो, मगर चुनाव में नेता नहीं, मतदाता ही 'बलवान' है। बैलेट पेपर से हुए इन चुनावों की तीन दिन तक चली मतगणना नेताओं को भी छकाती रही। सबसे निराशाजनक परिणाम कांग्रेस के लिए रहे। कांग्रेस के पास इनमें से चार सीटें थीं, लेकिन अब मात्र एक रह गई। कांग्रेस शासित कर्नाटक में चार सीटों के लिए चुनाव हुए, पर वहां उसका खाता तक नहीं खुला।

हालांकि नुकसान उसे एक सीट का ही हुआ, क्योंकि इनमें से तीन सीटें पहले से ही भाजपा के पास थीं और एक कांग्रेस के, जो इस बार भाजपा के मित्र दल जेडीएस ने छीन ली। फिर भी यह तो सच है कि चार राज्यों की 28 सीटों के चुनाव में कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई। भाजपा उसका मखौल उड़ाने से नहीं चूकी, पर कांग्रेस ने जो एकमात्र सीट जीती, वह नागपुर की है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र है। भाजपा के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी नागपुर ही है। नागपुर का परिणाम आने से पहले ही फडणवीस ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर पोस्ट करने का उतावलापन दिखाया, जिसे बाद में डिलीट करना पड़ा।

देखा जाए तो चारों ही राज्यों में मतदाताओं ने सत्ता को सबक सिखाया है। कर्नाटक में कांग्रेस की किरकिरी हुई तो महाराष्ट्र में भाजपा की अगुआई वाली महायुति की। ऐसे चुनावों में सत्तारूढ़ दल से हमेशा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहती है, लेकिन कांग्रेस तो अपनी पिछली सीट भी हार गई। इसे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उनके पूर्ववर्ती सिद्धरमैया के बीच सब कुछ ठीक न होने का नतीजा माना जा रहा है। दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच सहज संबंध आसान नहीं होते, लेकिन ऐसा करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवकुमार की ज्यादा है, जो कांग्रेस के संकटमोचक भी कहे जाते हैं। वैसे निराशाजनक प्रदर्शन के चलते असहज स्थिति कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए भी है, क्योंकि कर्नाटक उनका गृह राज्य है। महाराष्ट्र में पांच सीटों के लिए हुए चुनाव में विपक्षी गठबंधन तीन जीत गया, जबकि सत्तारूढ़ महायुति को दो सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। यहां शिंदे-शिवसेना की महत्वाकांक्षाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं तो सुनेत्रा पवार की एनसीपी भी वित्त मंत्रालय वापस पाने के लिए दबाव बना रही है। बुजुर्ग शरद पवार निश्चय ही अपने नियंत्रण वाली एनसीपी के प्रदर्शन से खुश होंगे।बिहार में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत बांकीपुर विधानसभा सीट हारने के बाद भाजपा को पटना विधान परिषद सीट पर भी मिली मात से नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों के लिए असहज स्थितियां पैदा हो गई हैं। जदयू में तो तकरार सड़क पर ही आ गई है। अधिकृत उम्मीदवार नीरज कुमार के विरुद्ध अनुज सिंह का समर्थन करने वाले बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन रार यहीं पर थमने के आसार नहीं।जीतने के बाद नीरज ने जिस तरह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को लेकर सवाल उठाए, वह अंतर्कलह का ही संकेत रहा। राजद और कांग्रेस में कलह भी इन चुनावों में सामने आ गई। सहमति न बन पाने पर दोनों अलग लड़े। राजद ने तो दो सीटें जीत कर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस पांच सीटों पर लड़ कर भी खाता नहीं खोल पाई। कभी चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीत के बाद इन चुनावों में भी एक सीट जीत कर सही राह पर होने का संकेत दिया है। अभी तक जनसुराज का उभार राजद के लिए ही खतरे की घंटी माना जा रहा था, लेकिन भाजपा को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा।सबसे दिलचस्प चुनाव परिणाम सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आए। यहां 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा छह, जबकि सपा पांच सीटें जीतने में सफल रही। यह आंकड़ा भाजपा की बढ़त तो बताता है, लेकिन विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले सपा का ऐसा प्रदर्शन सत्तारूढ़ दल के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए भी कि सपा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटें जीतने में सफल रही। सपा लखनऊ और आगरा की सीट भी जीत गई। इससे यह संकेत भी मिलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद भाजपा जरूरी सुधारात्मक कदम नहीं उठा पाई है।

अगर कुछ कदम उठाए भी गए तो उनके वांछित परिणाम अभी तक सामने आते नहीं दिखते। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर की यह टिप्पणी कि इन चुनावों में पढ़े-लिखे लोग वोट डालते हैं, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, हमारी राजनीति के सोच को भी दर्शाती है। बेशक विधान परिषद चुनाव में आम मतदाता वोट नहीं डालते, पर उनके बीच के ही पढ़े-लिखे लोग वोट डालते है, जिन्हें सामान्यतः भाजपा समर्थक भी माना जाता है। इसलिए ये चुनाव परिणाम सपा के लिए उत्साहवर्धक हैं। कांग्रेस ने भी सीटों के लिए दबाव न बनाकर समझदारी दिखाई। भाजपा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के संसदीय क्षेत्रों में हार गई तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में किसी तरह उसकी प्रतिष्ठा बची। चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल कम नहीं उठ रहे।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को भले ही 'अंगद का पांव' बताया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में ओबीसी-दलित छिटकते दिखे तो अब विधान परिषद चुनाव में टिकट वितरण में प्राथमिकता के बावजूद परंपरागत समर्थक सवर्ण भी दूर जाते दिखे। जाहिर है, यूजीसी जैसे मुद्दों पर परंपरागत समर्थकों में भी नाराजगी दूर करते हुए भाजपा को अपने समीकरण दुरुस्त करने होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिख रहा है।

भारत ने ई-वीजा के लिए 11 नए प्रवेश द्वार खोले

नई दिल्ली. भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए ई-वीजा व्यवस्था को और आसान बनाते हुए 11 नए अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बिंदुओं को इसके दायरे में शामिल किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को इन नए प्रवेश बिंदुओं को अधिसूचित किया. इसके साथ ही भारत में ई-वीजा धारकों के लिए प्रवेश और निकास की सुविधा देने वाले अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों और अन्य प्रवेश बिंदुओं की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है. सरकार के इस कदम से अब हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, सड़क सीमा चौकियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बिंदुओं के माध्यम से ई-वीजा लेकर भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, नए जोड़े गए 11 अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बिंदुओं में नौ स्थल सीमा चौकियां और दो हवाई अड्डे शामिल हैं. इनमें पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी, मणिपुर का मोरेह, मेघालय का डॉकी, पश्चिम बंगाल के जयगांव, हरिदासपुर, गेडे और घोजाडांगा, असम का दारंगा तथा अगरतला सहित अन्य प्रवेश बिंदु शामिल हैं. इन स्थानों को ई-वीजा धारक विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश और देश से बाहर जाने की सुविधा के लिए अधिकृत किया गया है.

नए प्रवेश बिंदुओं को शामिल किए जाने के बाद अब ई-वीजा के जरिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए कुल 88 अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बिंदु उपलब्ध हो गए हैं. इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 स्थल सीमा प्रवेश बिंदु शामिल हैं. इससे भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए प्रवेश के विकल्प पहले की तुलना में और व्यापक हो गए हैं.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से देश की वीजा व्यवस्था को उदार, सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है. इसका उद्देश्य वैध विदेशी यात्रियों के लिए भारत की यात्रा को आसान बनाना है. साथ ही आधुनिक तकनीकी ढांचे को मजबूत कर आंतरिक सुरक्षा को भी बेहतर बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है.सरकार के अनुसार, नए प्रवेश बिंदुओं को अधिसूचित करने का फैसला नए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इस नए कानून ने पहले लागू विदेशी अधिनियम की जगह ली है. अधिकारियों के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत हवाई, समुद्री, स्थल और रेल मार्गों से भारत में आने-जाने की व्यवस्था को एक समान ढांचे के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है.

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नए प्रवेश बिंदुओं की अधिसूचना से यात्रियों को अधिक स्पष्टता मिलेगी और अलग-अलग माध्यमों से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आव्रजन सुविधाओं को एक समान बनाने में मदद मिलेगी. इससे सीमा और प्रवेश बिंदुओं पर प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने की उम्मीद है.भारत में ई-वीजा व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी. उस समय यह सुविधा 43 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध थी. धीरे-धीरे इसका विस्तार किया गया और वर्तमान में 172 देशों के नागरिक भारत के लिए ई-वीजा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. सरकार ने इसे भारतीय वीजा व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है.ई-वीजा व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति यानी ईटीए जारी की जाती है. इसके माध्यम से विदेशी नागरिक भारत की यात्रा से पहले ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. यह व्यवस्था विशेष रूप से पर्यटन से जुड़े यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हुई है. इसके अलावा विद्यार्थी, चिकित्सा उपचार, समूह यात्रा और पारगमन सहित कई श्रेणियों के लिए भी ई-वीजा उपलब्ध है.वर्तमान में ई-वीजा की सुविधा 17 अलग-अलग श्रेणियों में उपलब्ध बताई गई है. इनमें पर्यटन, विद्यार्थी, चिकित्सा, समूह आगंतुक और पारगमन जैसी श्रेणियां शामिल हैं. सरकार का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था के विस्तार से विदेशी यात्रियों को भारत आने की प्रक्रिया में सुविधा मिली है और वीजा जारी करने की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक तकनीक आधारित हुई है.

कांग्रेस का चुनिंदा विरोधाभास- सीएम माझी

मुख्यमंत्री- ओडिशा। देश की राजधानी नई दिल्ली की सड़कों पर पिछले कुछ समय से मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन एवं नारेबाजी हो रही है। आरोप है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है और यह संवैधानिक संस्था सरकार के प्रभाव में काम कर रही है।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का तर्क है कि कल तक चुनाव आयोग निष्पक्षता का प्रतीक था, लेकिन आज उसकी स्वायत्तता खतरे में है। यह दावा सुनने में भले ही प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन निष्पक्षता की मांग करने वालों से यह पूछना भी जरूरी है कि क्या उन्होंने सत्ता में रहते हुए इन्हीं सिद्धांतों का पालन किया था?

लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की असली परीक्षा तब होती है, जब उनके फैसले राजनीतिक दलों की अपेक्षाओं के अनुरूप न हों। लेकिन क्या किसी संस्था की निष्पक्षता का पैमाना चुनावी नतीजों से तय किया जा सकता है? क्या जीत मिलने पर वही प्रक्रिया स्वीकार्य और हार होने पर संदिग्ध हो जाती है? चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस के मौजूदा रुख ने ऐसे ही बुनियादी सवाल खड़े किए हैं।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर बहस आज से शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में भी आयोग की नियुक्तियों, उसकी संरचना और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकारों को लेकर विवाद उठे थे। वर्ष 1989 में निर्वाचन आयुक्तों के अतिरिक्त पदों का सृजन, 1993 में टीएन शेषन के कार्यकाल के दौरान आयोग की संरचना में बदलाव और 2009 में नवीन चावला की नियुक्ति ऐसे प्रसंग हैं, जिन्हें वर्तमान बहस से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

इस पूरे विवाद में एक बुनियादी अंतर समझना जरूरी है कि आरोप और प्रमाण एक ही चीज नहीं हैं। चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के एसआइआर की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मगर न्यायिक जांच पूरी होने से पहले ही इस्तीफे की मांग को अंतिम निष्कर्ष की तरह पेश करना लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करता है।

नियुक्तियों में सरकारी प्रभाव = संविधान के अनुच्छेद 324 ने चुनाव आयोग को चुनाव संबंधित फैसले लेने की जिम्मेदारी दी है। लंबे समय तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर होती रही। इस व्यवस्था में संसद ने सात दशकों से अधिक समय तक नियुक्तियों की प्रक्रिया निर्धारित करने वाला अलग कानून नहीं बनाया। इस अवधि के बड़े हिस्से में कांग्रेस सत्ता में रही।

कांग्रेस नियुक्तियों में सरकारी प्रभाव को लेकर सवाल उठा रही है, तब यह पूछना स्वाभाविक है कि सत्ता में रहते हुए उसने इसे बदलने की पहल क्यों नहीं की। यदि नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार आवश्यक था, तो इसकी जिम्मेदारी उन सभी दलों की थी, जिन्हें लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिला।

अक्टूबर 1989 में लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले राजीव गांधी सरकार ने दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों के पद बनाए और एसएस धनोआ एवं वीएस सीगल को नियुक्त किया। नवंबर 1989 में चुनाव के बाद बनी नई सरकार ने कुछ ही सप्ताह में इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया। इस घटनाक्रम ने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया कि क्या चुनाव आयोग की संरचना में बदलाव संस्थागत जरूरतों के आधार पर किया गया था या सरकार और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बीच टकराव ने इसमें भूमिका निभाई थी?

वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम पारित किया। इसके तहत नियुक्तियों के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति का प्रविधान किया गया। यह नियुक्ति प्रक्रिया को वैधानिक आधार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रक्रिया में पहली बार विपक्ष के नेता को वैधानिक स्थान मिला। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में इस प्रक्रिया में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती थी। सरकार जिसे चुनती थी, देश को उसी पर भरोसा करना पड़ता था।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। क्या पात्र नागरिकों को गलती से सूची से बाहर कर दिया गया था और क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी थी, ये तथ्य से जु? सवाल हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में एसआइआर की समान प्रक्रिया अपनाई गई थी। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जब जीत हासिल की, तब कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा।

वहीं, पश्चिम बंगाल और असम में कांग्रेस हार गई, तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनावों में हेरफेर किया गया है।

जानकारी

सैलरी और पेंशन पर आ सकता है बड़ा अपडेट

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. 8वें वेतन आयोग ने अपने देशव्यापी दौरे के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 और 23 जून को अहम बैठक तय की है. इस बैठक में केंद्रीय सरकारी संस्थानों, कर्मचारी यूनियनों और संगठनों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.आयोग का मकसद कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों को सीधे सुनना है ताकि नई वेतन संरचना तैयार करते समय कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके. आयोग ने स्पष्ट किया है कि लखनऊ बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश की कर्मचारी यूनियनों को 10 जून 2026 तक एनआईसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.आयोग ने अपॉइंटमेंट प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया है. यूनियनों को पहले अपना मांग पत्र आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना होगा. मांग पत्र सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक यूनिक मेमो आईडी जारी की जाएगी. इसी मेमो आईडी के जरिए यूनियनें बैठक के लिए अपॉइंटमेंट ले सकेंगी.इस बीच आयोग ने सभी केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन्स से 31 मई 2026 तक अपनी सिफारिशें और मांग पत्र जमा करने को कहा है.

देश के बड़े कर्मचारी संगठन जैसे एनसी-जेसीएम और एआईडीईएफ

शिक्षा

तराई की खुशबू से भरपूर लखीमपुर खीरी के कच्चे केले के कोफ्ते

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी सिर्फ अपनी हरियाली, तराई और गन्ने की खेती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक स्वादों के लिए भी खास पहचान रखता है. नेपाल सीमा से सटे इस इलाके की रसोई में मिट्टी की सोंधी खुशबू, देसी मसालों का संतुलन और घर जैसा स्वाद हर व्यंजन में महसूस होता है. इन्हीं पारंपरिक व्यंजनों में ÷कच्चे केले के कोफ्ते÷ ऐसी शाही डिश मानी जाती है, जो आज भी यहां के केले का इस्तेमाल सिर्फ साधारण सब्जी के रूप में नहीं, बल्कि बेहद खास अंदाज में किया जाता है. यहां बनने वाले केले के कोफ्ते इतने मुलायम और रेशमी होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं. इस डिश की सबसे बड़ी खासियत इसका संतुलित स्वाद है, जिसमें मसाले केले के प्राकृतिक स्वाद को दबाते नहीं बल्कि उसे और निखार देते हैं.सबसे पहले कच्चे केलों को हल्का उबाल लें. ध्यान रखें कि केले पूरी तरह गलें नहीं, बस इतने नरम हो जाएं कि आसानी से मैश किए जा सकें. अब केले का छिलका हटाकर उन्हें अच्छे से मैश करें. इसमें भुना बेसन, हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, हींग, नमक और लाल मिर्च डालकर मिश्रण तैयार करें.

34 लाख रुपये तक की कटौती, भारत में असेंबलिंग शुरू होते ही बदले दाम

नई दिल्ली. लग्जरी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिएको लेकर बड़ी खबर सामने आई है. ने भारत में अपनी लोकप्रिय ऑफ-रोड की लोकल असेंबली शुरू कर दी है. इसके बाद कंपनी ने चुनिंदा वेरिएंट की कीमतों में 34 लाख रुपये तक की कटौती की है. कीमतों में इस बदलाव से पहले के मुकाबले अधिक किफायती हो गई है, हालांकि यह अब भी प्रीमियम लग्जरी श्रेणी में आती है. कंपनी अब महाराष्ट्र के पुणे स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 110 के चुनिंदा वेरिएंट को असेंबल कर रही है. पहले इन गाड़ियों को पूरी तरह निर्मित यूनिट यानी ष्टक्र के रूप में विदेश से भारत लाया जाता था. लोकल असेंबली से आयात लागत में कमी आने की उम्मीद है, जिसका फायदा ग्राहकों को कम कीमत के रूप में मिला है. नई कीमतों के साथ एक बार फिर भारतीय लग्जरी बाजार में चर्चा का विषय बन गई है.कीमतों में आई कमी का सबसे बड़ा कारण इसकी भारत में लोकल असेंबली को माना जा रहा है. अब तक कंपनी इस को स्लोवाकिया से पूरी तरह निर्मित यूनिट के रूप में भारत में आयात करती थी. इस प्रक्रिया में आयात शुल्क और अन्य संबंधित लागतें वाहन की अंतिम कीमत को प्रभावित करती थीं.



15 नवंबर को आगरा में होगा दलित सम्मेलन 20 से अधिक जिलों में सपा चला रही जनसंपर्क अभियान

जितेन्द्र पमनानी। सिटी चीफ

आगरा। जीआईसी मैदान में 15 नवंबर को होने वाले दलित सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी ने महानगर कैंप कार्यालय पर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। घर-घर जाकर सम्मेलन के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 20 से अधिक जिलों में संपर्क अभियान चल रहा है। शहरी क्षेत्र के लिए निर्णय हुआ कि पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दलित बहुल बस्तियों एवं मोहल्लों में घर-घर जाकर सघन जनसंपर्क करेंगे। दलित चेतना एवं जागरूकता अभियान के जरिये आमजन को डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों, सांविधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय से जोड़ा जाएगा। वहीं महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि संविधान, लोकतंत्र और अधिकारों की रक्षा के लिए दलित, पिछड़े व शोषित समाज को एकजुट होना होगा। बैठक में रामसहाय यादव, पुष्पेंद्र शर्मा, रवि मेहरा, नितिन वर्मा, नरेंद्र नंद, मनोज गुप्ता, बबलू बाल्मीकि, बलीशेर नेताजी, जिया चौधरी, समीर अब्बास, फहीम उस्मानी और हरीश प्रजापति सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरता गद्दी दिवस पर 11 नवंबर को होगा भव्य गुरमत समागम प्रेस वार्ता में किया कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन, देश-विदेश से रागीजन एवं कथा वाचक संगत को करेंगे निहाल

जितेंद्र पमनानी। सिटी चीफ



आगरा, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरता गद्दी दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 11 नवंबर को गुरुद्वारा दशमेश दरबार, आगरा की ओर से भव्य गुरमत समागम का आयोजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ किया जाएगा, मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने पत्रकार साथियों को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी तथा आयोजन के पोस्टर का विमोचन किया,कमेटी के प्रधान हरपाल सिंह ने बताया कि यह पावन आयोजन 11 नवंबर, बुधवार को शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कोठी नंबर 23, माल रोड, आगरा (पुरातत्व विभाग कार्यालय के पीछे) आयोजित होगा, समागम में सोदर रहरास साहिब, अमृतमयी गुरबाणी कीर्तन एवं गुरमत विचारों के माध्यम से संगत को गुरु चरणों से जोड़ा जाएगा,समागम में विशेष रूप से भाई साहिब भाई जसवंत सिंह (दरबार साहिब मंजी साहिब अमृतसर वाले), भाई साहिब भाई तरनवीर सिंह रब्बी, (लुधियाना वाले) एवं वीर हरजिंदर सिंह जी (हजूरी रागी, दशमेश दरबार) अपनी मधुर गुरबाणी एवं कीर्तन से संगत को निहाल करेंगे, कार्यक्रम में कथा वाचन एवं गुरमत विचारों का भी विशेष आयोजन रहेगा, समागम के उपरांत गुरु का अटूट लंगर वितरित किया जाएगा,इस धार्मिक आयोजन में गुरुद्वारा गुरु का ताल के संत बाबा प्रीतम सिंह जी का विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, आयोजकों ने समस्त गुरु नानक नाम लेवा संगत से परिवार सहित पहुंचकर गुरमत समागम की खुशियां प्राप्त करने की अपील की,प्रधान हरपाल सिंह,राजू सलूजा, मलकीत सिंह, श्याम भोजवानी, गुरिंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह लवली,देवेंद्र सिंह,इंद्रजीत सिंह,सुरेंद्र सिंह ला?ी,हरजिंदर कौर, हरविंदर कौर,स्वरन कौर, मनसा सिंह,रानी कालरा,कृपाल सिंह,मनदीप सिंह, सनी सिंह समस्त प्रबंधक कमेटी

ग्वालियर में ऑनलाइन दोस्ती के बाद नाबालिग से दुष्कर्म, 2 लाख नकद और पुश्तैनी गहने लूटने का आरोप

अरविंद सिंह पवैया। सिटी चीफ



ग्वालियर, ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और घर से नकदी व सोने के गहने ले जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की सोशल मीडिया के जरिए नितेश शर्मा से पहचान हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उससे प्यार का इजहार किया। आरोप है कि 15 जनवरी 2026 को छात्रा की मां के काम पर जाने के बाद आरोपी अपने साथी के साथ घर में घुसा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींच लीं। इसके बाद 27 फरवरी को आरोपी ने दोबारा घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी घर में रखे 2 लाख रुपए नकद और पुश्तैनी सोने की झुमकी भी ले गया।एसपी जयराज कुबेर ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट के आदेश के पालन में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

बडवानी दीपावली से पहले बड़वानी में यातायात व्यवस्था सुधारने की पहल, पुलिस और नगर पालिका ने दुकानदारों से किया सहयोग का आग्रह

अतुल कुमावत। सिटी चीफ



बड़वानी, दीपावली का पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। त्योहार के दौरान खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में नागरिक बाजार पहुंचते हैं। ऐसे में सभी को बेहतर और सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़वानी यातायात पुलिस एवं नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से पहल की जा रही है।इसी क्रम में मंगलवार को कचहरी रोड, पाला बाजार, रामदेव मंदिर रोड एवं एमजी रोड पर यातायात पुलिस और नगर पालिका की टीम ने दुकानदारों से चर्चा कर सहयोग का आग्रह किया। इस दौरान यातायात थाना प्रभारी विनोद बघेल ने दुकानदारों से अपील की कि वे अपनी दुकानों के बाहर सामान व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि बाजारों में आने वाले ग्राहकों, राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिल सके।

लखीसराय जिले में सनसनी दो अलग-अलग गांवों से दो शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस व FSL की टीम

उत्तम कुमार। सिटी चीफ

लखीसराय (बिहार), लखीसराय जिला अंतर्गत दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मंगलवार की सुबह दो शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पहली घटना सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के निस्ता गांव की है, जहां एक बगीचे से किशोर का संदिग्ध शव बरामद किया गया। वहीं दूसरी घटना तेतरहट थाना क्षेत्र के खैरी गांव की है, जहां बगीचे में एक युवक का शव फंदे से लटकता पाया गया। दोनों ही मामलों में पुलिस हत्या और आत्महत्या समेत तमाम बिंदुओं पर गहन छानबीन कर रही है। सूर्यगढ़ा में किशोर की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका जानकारी के अनुसार, सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के निस्ता और टोलरपुर गांव के बीच स्थित एक बगीचे से मंगलवार की सुबह एक किशोर का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान निस्ता गांव निवासी मैनेजर यादव के पुत्र पिंकेश कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने



पुरानी रंजिश और विवाद को लेकर पिंकेश की हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है।मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ-साथ विधि-विज्ञान प्रयोगशाला (स्नस्रु) की विशेष तकनीकी टीम को भी मौके पर बुलाया गया। स्नस्रु की टीम ने घटनास्थल पर डेरा डालकर वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके।तेतरहट के खैरी गांव में पेड़ से लटकता मिला युवक का शवइधर, तेतरहट थाना क्षेत्र के खैरी गांव स्थित एक बगीचे में पेड़ से लटकती एक युवक की लाश को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद तेतरहट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस हर संभावित एंगल से मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि यह मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई साजिश है।लखीसराय पुलिस ने दोनों ही मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस बल के साथ छानबीन तेज कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और स्नस्रु की वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दोनों मौतों के असली कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा।

भाकियू वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने देश के अन्नदाता किसानों की समस्याओं व पृथक राज्य की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन अपर आयुक्त को सौंपा

गौरव सिंघल। सिटी चीफ

सहारनपुर (उ.प्र.), भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मंडलायुक्त कार्यालय पर अपर आयुक्त रमेश यादव से देश के अन्नदाता किसानों की समस्याओं व पृथक राज्य की मांग को लेकर मिला और उन्हें समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के अन्नदाता किसानों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। जिसे प्रधानमंत्री जी तत्काल समाप्त करें। जब देश के चंद कॉर्पोरेट घरानों के कर्ज समाप्त हो सकते हैं तो अन्नदाता किसानों के क्यों नहीं। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है इसलिए उत्तर प्रदेश को चार भागों में विभाजित करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर



पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, आगरा और बरेली में एम्स की स्थापना कराई जाए। सहारनपुर में आईआईएम की स्थापना कराई जाए, मेरठ में तत्काल प्रभाव से मिनी सचिवालय और हाई कोर्ट की स्थापना कराई जाए।राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि देश के अन्नदाता किसानों के सभी कर्ज समाप्त कराए जाएं।अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सीटू प्लस 50त्न के अनुसार किसानो की फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाए। राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन किया जाए। 58 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग किसान व मजदूरों को ?10000 प्रति माह पेंशन दिलाई जाए।सभी हाईवे और सड़कों से टोल टैक्स समाप्त कराये जाए। प्रदेश और देश में उद्योग विकास सड़क व अन्य कार्यों में किसानों की भूमि अधिग्रहण होने पर उन्हें प्राइवेट पार्टनरशिप करके आजीवन 10त्न का लाभ दिलाया जाए और किसानों की भूमि बाजार मूल्य से चार गुना पर अधिग्रहित की जाए।

सहारनपुर में जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय ई-कवच प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

गौरव सिंघल। सिटी चीफ

सहारनपुर (उ.प्र.)। जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि हेतु ई-कवच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (ञ्जह्लड्डद्बठ्ठद्बद्द श्रद्ध ञ्जह्लड्डद्बठ्ठद्दह्ह्ड्ड ञ्जभञ्ज) का आयोजन होटल सरोवर पोर्टिको, सहारनपुर में यूपी-टीएसयू के सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. लोकेश चंद्र गुप्ता, अपर निदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य) द्वारा की गई। कार्यक्रम में डॉ. डी.के. सिंह एवं डॉ. कुमुद, संयुक्त निदेशक सहित मंडलीय, जनपदीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर निदेशक ने ई-कवच डिजिटल प्लेटफॉर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आंकड़ों का रियल टाइम



संकलन, प्रभावी अनुश्रवण, सेवा प्रदायगी में सुधार तथा साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।प्रशिक्षण के दौरान मंडलीय परियोजना प्रबंधक रंजीत द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन संबंधी पहलुओं पर जानकारी दी गई। मंडलीय एम एंड ई विनोद कुमार द्वारा ई-कवच प्लेटफॉर्म की तकनीकी कार्यप्रणाली, विभिन्न मॉड्यूल, डाटा प्रविष्टि एवं रिपोर्टिंग की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त सुश्री पारुल एवं यूपी-टीएसयू के प्रतिनिधि देवेंद्र द्वारा तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया गया। प्रशिक्षण में ई-कवच के सभी प्रमुख मॉड्यूल एवं कार्यात्मक पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही डाटा की शुद्धता, समयबद्ध प्रविष्टि, रियल टाइम रिपोर्टिंग एवं नियमित अनुश्रवण के महत्व पर विशेष बल दिया गया।कार्यक्रम में प्रतिभागियों द्वारा उत्साहपूर्वक सहभागिता की गई तथा विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं उपयोग की जानकारी प्राप्त की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मंडल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर डिजिटल दक्षता को सुदृढ़ करना तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना रहा।

कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार आयोजित जनसुनवाई में आए 50 आवेदन

बडवानी 03 नवंबर 2026/प्रति मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय बडवानी में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की शिकायतें सुनीं एवं संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों पर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंगलवार जनसुनवाई में कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए।जनसुनवाई के दौरान ठीकरी तहसील के ग्राम पलासिया के रामदेवपुरा निवासी संगीता (पत्नी स्व. श्याम चौहान) ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। संगीता चार बच्चों की माता है और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही है। उसने आवेदन में अवगत कराया कि उसे पात्रता के बावजूद नि:शुल्क खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, पति की मृत्यु के उपरांत भी उसे कल्याणी (विधवा) पेंशन व आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे सूची में भी उसका नाम दर्ज नहीं है।

कलेक्टर जयति सिंह ने महिला की स्थिति एवं समस्या को संवेदनशीलता से संज्ञान लेते हुए सामाजिक न्याय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक तत्परता के परिणामस्वरूप महिला को तुरंत निम्नलिखित राहत प्रदान की गई।कल्याणी पेंशन स्वीकृत- जिला सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ तत्काल स्वीकृत किया गया।नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदाय-जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा महिला के दस्तावेज सत्यापन का कार्य तुरंत पूर्ण कराया गया। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होने पर आगामी माह से उसे नियमित नि:शुल्क खाद्यान्न की पात्रता पर्ची प्राप्त होने लगेगी।स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला की दो बालिकाओं को स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।2. आवेदक राजु पिता हीरालाल येसीकर ने आपसी समझौते के बावजूद पडोसी खातेदारों द्वारा खेत पर आने-जाने का रास्ता रोके जाने और बोरवेल का पानी बंद करने की शिकायत की है। पूर्व में नोटरी के समक्ष हुए समझौते के अनुसार 10-10 फीट जमीन छो?कर रास्ता तय हुआ था, जिसके पालन और न्याय की मांग की गई है। । इसके बावजूद, पढोसी खातेदारों द्वारा रास्ता नहीं दिया जा रहा है, वाहन लाने से रोका जा रहा है। इस पर जनसुनवाई पर अपर कलेक्टर हेमलता सोलंकी ने प्रकरण नायब तहसीलदार खेतिया को प्रेषित कर दोनों पक्षों को समक्ष में सुन कर निराकरण करने के निर्देश दिए ।जनसुनवाई में मुख्य रूप से खेत में आने जाने का रास्ता दिलवाए जाने, राजमिस्त्रियों की मजदूरी राशि का भुगतान, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार, भू-अर्जन, स्वामित्व योजना ,अवैध कब,भूमि रिकार्ड संशोधन, पुलिस विभाग से संबंधित आवेदन अर्पित गुप्ता, अपर कलेक्टर हेमलता सोलंकी, एसडीएम बवानी भूपेन्द्र रावत, तहसीलदार राहुल सोलंकी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

ऑल एबिलिटी नेशनल चैंपियनशिप 2026 गुजरात को 7 विकेट से हराकर जम्मू-कश्मीर दिव्यांग क्रिकेट टीम ने फाइनल में बनाई जगह, अब तक अजेय रहा सफर

मोहन सिंह। सिटी चीफ

जम्मू-कश्मीर, जम्मू-कश्मीर दिव्यांग क्रिकेट टीम ने ऑल एबिलिटी नेशनल चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए गुजरात की टीम को 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। जम्मू-कश्मीर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। टीम ने अब तक टूर्नामेंट में अपने सभी मुकाबले जीतकर अजेय रहने का गौरव हासिल किया है।

मुकाबले में जम्मू-कश्मीर के कप्तान सैयद शाह अजीज शाह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत गुजरात की टीम 12.1 ओवर में 81 रन पर सिमट गई। शानदार प्रदर्शन के लिए सैयद शाह अजीज शाह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।



वहीं नियाज अहमद ने 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि इम्तियाज गुल ने 2.1 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट झटके।

82 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जम्मू-कश्मीर की टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 8 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

राहुल शर्मा ने 19 गेंदों पर 6 चौकों और एक छक्के की मदद से शानदार 32 रन बनाए। वहीं इम्तियाज गुल ने 9 गेंदों पर नाबाद 20 रन और आकिब मलिक ने 11 गेंदों पर 17 रन का योगदान दिया।इस जीत के साथ जम्मू-कश्मीर दिव्यांग क्रिकेट टीम ने 4 नवंबर 2026 को होने वाले ग्रैंड फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।3 नवंबर को गुजरात और महाराष्ट्र के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम 4 नवंबर को फाइनल में अजेय जम्मू-कश्मीर की टीम से खिताब के लिए भिड़ेगी।जम्मू-कश्मीर की टीम पूरे आत्मविश्वास और जीत के संकल्प के साथ फाइनल में उतरेगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 5.0 का शुभारंभ किया

गोपाल गुप्ता। सिटी चीफ

उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा पेंशनभोगियों की सुविधा और पेंशन सेवाओं को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान-5.0 का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के माध्यम से रेलवे पेंशनभोगियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री अमित सुदर्शन के अनुसार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान-5.0 का शुभारंभ उत्तर पश्चिम रेलवे के लेखा एवं कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी डॉ. विष्णु बजाज तथा मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री विनोद कुमार की अध्यक्षता में किया गया।

ऑपरेशन ग्रीन स्ट्राइक बड़वानी पुलिस का मादक पदार्थ तस्करों पर बड़ा प्रहार, 16.70 लाख मूल्य के 130 हरे गांजे के पौधे जप्त

अतुल कुमावत। सिटी चीफ

बड़वानी/ पानसेमल, पुलिस महानिरीक्षक (ग्रामीण जोन, इंदौर) अनुराग एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक (निमाड़ रेंज, खरगोन) सिमाला प्रसाद के दिशा-निर्देशों तथा प्रभारी पुलिस अधीक्षक (बड़वानी) विनोद कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध खेती के विरुद्ध विशेष %ऑपरेशन ग्रीन स्ट्राइक% चलाया जा रहा है।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (राजपुर) श्री बी. एल. अटोदे के मार्गदर्शन में थाना पानसेमल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गांजे की अवैध खेती का पर्दाफाश किया है।दिनांक 02.11.2026 को थाना प्रभारी पानसेमल रेवाराम चौहान के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम की जा रही है।सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश दी। मौके से अवैध रूप से उगाए गए 130 हरे गांजे के पौधे जप्त किए गए, जिनका कुल वजन 1 क्विंटल 67 किलोग्राम तथा अनुमानित बाजार मूल्य ?16,70,000/- (सोलह लाख सत्तर हजार रुपये) है।



झालोल में ब्लॉक स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता पंच गौरव योजना के तहत ग्रामीण प्रतिभाओं को मिला बडा मंच

गोपाल गुप्ता। सिटी चीफ

उदयपुर। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पंच गौरव योजना एवं एक जिला एक खेल के अंतर्गत उदयपुर जिले के जनजातीय व ग्रामीण अंचलों (झोल, कोटा तथा फलासिया) की ब्लॉक स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता (टैलेंट सर्च) का सफल आयोजन सोनी रिसॉर्ट, झोल में किया गया। यह प्रतियोगिता जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल तथा उदयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास प्रन्यास आयुक्त अभिषेक खन्ना के दिशा-निर्देशों के क्रम में और जिला खेल अधिकारी डॉ. महेश पालीवाल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व स्थानीय प्रतिभाओं को तराशकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं का चयन आगामी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। पिछले वर्ष भी चयनित तैराकों के लिए उदयपुर के महाराणा प्रताप खेलगांव में आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर विशेषज्ञों द्वारा एडवांस ट्रेनिंग दी गई थी।

झोल ब्लॉक में बालक वर्ग के तहत मदन वडेरा, एनोश सरेड और भावेश गायरी प्रथम रहे। रमेश कपाया, जितेन्द्र कुमार और भगवती द्वितीय रहे। पंकज, संजय खराडी और मनिष परमार ने तृतीय



स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में रमीला कुमारी, लक्ष्मी कुमारी और वसुन्धरा लक्ष्मी प्रथम रहीं। ज्योती, दुर्गा, सुमित्रा, धुलकी, कैलाशी और कावली द्वितीय स्थान पर रहीं।

कोटा ब्लॉक में बालिका वर्ग के तहत सजना, जिया कुमारी, कपिला और प्रियंका प्रथम स्थान पर रहीं। रानी, त्रिपुरी, ललिता और सोनिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बालक वर्ग में नारायण लाल, राहुल और महेन्द्र प्रथम रहे। दिलीप कुमार, विमल और किशन द्वितीय तथा अर्जुनलाल, रमेश और करण तृतीय स्थान पर रहे।

इसी प्रकार फलासिया ब्लॉक में बालक वर्ग में सुभाष, विजेश, जितेन्द्र, प्रवीण और जितेश प्रथम रहे। मोहित, सिद्धार्थ, अंकित खराडी, हिम्मत, युवराज सिंह और रघुवीर सिंह ने द्वितीय स्थान पाया। बालिका वर्ग में सपना दामा, कल्पना, प्रियंका और मनीषा प्रथम रहीं। सुर्या, ऐश्वर्या, आरती और कान्ता तृतीय स्थान पर रहीं। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी कार्यालय से तैराकी प्रशिक्षक गगन व्यास और राधेश्याम सुथार सहित विभिन्न विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक जैसे रमेश कुमार दरांगी, मावाराम दामा, भूरीलाल खराडी, भगवान लाल मेघवाल, जगदीश जोशी, नटवर सिंह झाला और कन्हैयालाल गमार उपस्थित रहे।कार्यक्रम के दौरान झा?ोल के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोरध्वज व्यास एवं मुख्य अतिथि व समाजसेवी यशवंत सोनी ने विजेताओं को मेडल व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। यशवंत सोनी ने युवाओं को खेलों में निरंतर रुचि बनाए रखने के लिए प्रेरित किया और स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से सरकारी नौकरियों में मिलने वाले अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने अपने संस्मरण साझा करते हुए बताया कि वे स्वयं 8 वर्ष की अल्पायु से ही फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और तैराकी में कई पदक हासिल कर चुके हैं।



बालघर विद्यालय में स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन विद्यार्थियों के स्वस्थ जीवन की दिशा में सराहनीय पहल

अश्विनी वालिया। सिटी चीफ

कुरुक्षेत्र (हरियाणा), श्रीमद्भगवदगीता प्राथमिक विद्यालय में आज दिनांक 3 नवंबर 2026 विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉ दीपक शर्मा जी द्वारा विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच की गई। सर्वप्रथम तिलक के साथ उनका स्वागत किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्या चेतना वशिष्ठ एवं विद्यालय प्रबंधक श्री जीवन मौदगिल जी द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया । उनके द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की गई।शिविर के दौरान बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य जाँच, आँखों, दाँतों एवं व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित जांच व आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने, नियमित व्यायाम करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समयाओं के प्रति सजग रहने की सलाह दी गई।इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्या जी ने डॉ दीपक शर्मा का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया तथा कहा कि बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य उनके सर्वांगीण विकास का आधार है।यह स्वास्थ्य जाँच शिविर विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक रहा। इस पहल के माध्यम से बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।

सहारनपुर में पांच स्थानों पर शर्तों के साथ अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस की तीन दिन के लिए मिली अनुमति

गौरव सिंघल। सिटी चीफ

सहारनपुर (उ.प्र.), जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार चौहान के निर्देशानुसार दीपावली पर्व पर नगर क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस 06 नवम्बर से 08 नवम्बर तक मात्र तीन दिन के लिए जारी किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। प्रभारी अधिकारी आयुद्ध कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना जनकपुरी क्षेत्रान्तर्गत



महाराज सिंह कॉलेज ग्राउण्ड में 45, थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत जे0वी0जैन डिग्री कॉलेज के मैदान में 36, कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जी0जी0आई 0सी0 ग्राउण्ड में 26, थाना कुतुबशेर क्षेत्रान्तर्गत सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में 37 एवं थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत आईटीआई दिल्ली रोड के खाली मैदान में 25 दुकानें लगाने के लिए अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस निर्गत किए गये है। कुलदीप सिंह ने बताया कि महाराज सिंह कॉलेज ग्राउण्ड में 26, जे0वी0जैन डिग्री कॉलेज के मैदान में 32 एवं आईटीआई दिल्ली रोड के खाली मैदान में 16 दुकानें आरक्षित करते हुए शेष दुकानें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित कर दी जाएगी। उन्होने निर्देश दिए कि लाईसेंसी द्वारा अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर स्वयं आतिशबाजी व्यवसाय किया जाएगा। यदि कार्यस्थल पर आतिशबाजी लाईसेंसी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति व्यवसाय करता हुआ पाया जाता है तो तत्काल लाईसेंस निरस्त कर आतिशबाजी सामग्री को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होने निर्देश दिए कि सभी लाईसेंसी अग्निशमन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

आपदा प्रबंधन कार्यशाला एवं अग्निशमन ड्रिल का आयोजन

अतुल कुमावत। सिटी चीफ



बडवानी। पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय में एक दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला एवं अग्निशमन ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में विद्यालय के प्राचार्य जितेंद्र सिंह, समस्त शिक्षकगण और बडी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को अत्यंत सरल भाषा में आपदा प्रबंधन का महत्व, सुरक्षा के उपाय, और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी गई। इसके साथ ही, आग लगने, भूकंप जैसी प्राकृतिक व मानव-निर्मित आपदाओं के समय स्वयं का तथा अपने परिजनों का सुरक्षित बचाव करने के व्यावहारिक तौर-तरीके (सिखलाई) बताए गए।कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों और शिक्षकों को अग्निशमन से जुडे उपकरणों के उपयोग की जानकारी देते हुए एक लाइव ड्रिल (अग्निशमन ड्रिल) भी करवाई गई। यह संपूर्ण प्रशिक्षण जिला सेनानी बवानी के कुशल नेतृत्व में एनडीआरएफ टीम और कंपनी कमांडर मुकेश मीणा द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रकार के आयोजनों से विद्यालयीन विद्यार्थियों में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जागरूकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटन के लिए टिकट दरें निर्धारित कोर जोन में ताला, मगधी और खितौली से पर्यटक कर सकेंगे जंगल सफारी

संजीव कुमार निगम। सिटी चीफ

शहडोल, संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व श्री अनुपम सहाय ने बताया है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए कोर एवं बफर जोन में जंगल सफारी की टिकट धारण क्षमता तथा भ्रमण की दरें निर्धारित हैं। कोर जोन में ताला, मगधी एवं खितौली तथा बफर जोन में धमोखर, जोहिला एवं पनपथा क्षेत्र में पर्यटक निर्धारित दरों पर पार्क भ्रमण का आनंद ले सकते हैं।कोर जोन में सुबह की पारी के लिए ताला में 28, मगधी में 26 तथा खितौली में 21 वाहनों की क्षमता निर्धारित है। इस प्रकार कोर जोन में सुबह की पारी में कुल 75 तथा शाम की पारी में 72 वाहनों की टिकट धारण क्षमता है।बफर जोन में धमोखर, जोहिला एवं पनपथा प्रत्येक क्षेत्र में सुबह और शाम की पारी के लिए 20-20 वाहनों की क्षमता निर्धारित है। इस प्रकार बफर जोन में सुबह एवं शाम की पारी में 60-60 वाहनों की क्षमता है। कोर एवं बफर जोन को मिलाकर कुल टिकट धारण क्षमता 267 वाहनों की है।ताला, मगधी एवं खितौली कोर जोन में भारतीय पर्यटकों के लिए अधिकतम 6 व्यक्तियों वाले पूरे वाहन का टिकट 2,690 रुपये निर्धारित है। प्रीमियम दिवस पर यह दर 3,350 रुपये है। विदेशी पर्यटकों के लिए पूरे वाहन का टिकट 5,330 रुपये तथा प्रीमियम दिवस पर 6,650 रुपये निर्धारित है।12 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों के लिए एक सीट का टिकट भारतीय पर्यटकों हेतु 450 रुपये तथा विदेशी पर्यटकों हेतु 890 रुपये है। प्रीमियम दिवस पर यह दर क्रमशः 560 रुपये एवं 1,110 रुपये है।इसी प्रकार 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक सीट का टिकट भारतीय पर्यटकों हेतु 230 रुपये तथा विदेशी पर्यटकों हेतु 450 रुपये निर्धारित है। प्रीमियम दिवस पर बच्चों की टिकट दर क्रमशः 285 रुपये एवं 560 रुपये है।

कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार आयोजित जनसुनवाई में आए 50 आवेदन प्रशासनिक तत्परता से संगीता को मिला कल्याणी पेंशन, खाद्यान्न और स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ

अतुल कुमावत। सिटी चीफ

बडवानी, बडवानी 03 नवंबर 2026/प्रति मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय ब?वानी में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की शिकायतें सुनीं एवं संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों पर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंगलवार जनसुनवाई में कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए।

1.संवेदनशील पहलः- जनसुनवाई में पहुंची श्रीमती संगीता को तत्काल मिला शासन की योजनाओं का लाभजनसुनवाई के दौरान ठीकरी तहसील के ग्राम पलासिया के रामदेवपुरा निवासी संगीता (पत्नी स्व. श्याम चौहान) ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। संगीता चार बच्चों की माता है और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही है। उसने आवेदन में अवगत कराया कि उसे पात्रता के बावजूद निःशुल्क खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, पति की मृत्यु के उपरांत भी उसे कल्याणी (विधवा) पेंशन व आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे सूची में भी उसका नाम दर्ज नहीं है।

कलेक्टर जयति सिंह ने महिला की स्थिति एवं समस्या को संवेदनशीलता से संज्ञान लेते हुए सामाजिक न्याय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही



त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक तत्परता के परिणामस्वरूप महिला को तुरंत निम्नलिखित राहत प्रदान की गई।

कल्याणी पेंशन स्वीकृत- जिला सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ तत्काल स्वीकृत किया गया।

निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय- जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा महिला के दस्तावेज सत्यापन का कार्य तुरंत पूर्ण कराया गया। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होने पर आगामी माह से उसे नियमित निःशुल्क खाद्यान्न की पात्रता पर्ची प्राप्त होने लगेगी।

स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला की दो बालिकाओं को स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. आवेदक राजु पिता हीरालाल येसीकर ने आपसी समझौते के बावजूद प?ोसी खातेदारों द्वारा खेत पर आने-जाने का रास्ता रोके जाने और बोरवेल का पानी बंद करने की शिकायत की है। पूर्व में नोटरी के समक्ष हुए समझौते के अनुसार 10-10 फीट जमीन छोडकर रास्ता तय हुआ था, जिसके पालन और न्याय की मांग की गई है। । इसके बावजूद, पडोसी खातेदारों द्वारा रास्ता नहीं दिया जा रहा है, वाहन लाने से रोका जा रहा है। इस पर जनसुनवाई पर अपर कलेक्टर हेमलता सोलंकी ने प्रकरण नायब तहसीलदार खेतिया को प्रेषित कर दोनों पक्षों को समक्ष में सुन कर निराकरण करने के निर्देश दिए ।

जनसुनवाई में मुख्य रूप से खेत में आने जाने का रास्ता दिलवाए जाने, राजमिस्त्रियों की मजदूरी राशि का भुगतान, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार, भू-अर्जन, स्वामित्व योजना,अवैध कब,भूमि रिकार्ड संशोधन, पुलिस विभाग से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।

जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ श्री अर्पित गुप्ता, अपर कलेक्टर हेमलता सोलंकी, एसडीएम बडवानी भूपेन्द्र रावत, तहसीलदार राहुल सोलंकी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही, अन्य विकासखण्डों एवं जनपदों के अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

चिब बिरादरी की एकजुटता और विकास के लिए मिलकर करेंगे काम - सुमन सिंह

मोहन सिंह। सिटी चीफ

अखनूर। चिब बिरादरी की मासिक बैठक मंगलवार को बाबा धर्मचंद जी देवस्थान, नड़ दा खू में पूर्व मंत्री एवं बिरादरी के मुख्य संरक्षक आरएस चिब की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नवनियुक्त प्रधान सोहन सिंह उर्फ सुमन सिंह सहित बिरादरी के कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन की मजबूती, देवस्थान के विकास और बिरादरी में चल रहे विवाद को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए आरएस चिब ने कहा कि बिरादरी की एकता और संस्थागत व्यवस्था बनाए रखना समय की आवश्यकता है। उन्होंने देवस्थान के इतिहास और पंजीकरण की जानकारी देते हुए बताया कि इसका आधिकारिक पंजीकरण %बाबा धर्म चंद जी देवस्थान,



नड़ दा खू% के नाम से है। उन्होंने मीडिया के समक्ष पंजीकरण संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में देवस्थान पर सुविधाओं का अभाव था, लेकिन बिरादरी के सहयोग से धन एकत्रित कर यहां व्यापक विकास और नवीनीकरण के कार्य करवाए गए।पूर्व प्रधान शमशेर सिंह चिब पर निशाना साधते हुए आरएस चिब ने कहा कि प्रधान का कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित होना चाहिए, जबकि शमशेर सिंह करीब सात वर्षों तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने कहा कि बिरादरी की बेहतरी के लिए नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक था और इसी उद्देश्य से सुमन सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए नामपट्टिका को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया।कमल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बिरादरी के हितों को व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर रखा जाना चाहिए।

त्योहारों को देखते हुए गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए बन रहा होल्डिंग एरिया

गोपाल गुप्ता। सिटी चीफ

त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की जा रही है। इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने हेतु श्री पंकज शर्मा, महाप्रबंधक /उत्तर पश्चिम रेलवे ने मंगलवार को गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।



स्टेशन पर रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू कर भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जाएगा, ताकि यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े। आगामी त्योहारों के दौरान स्टेशन पर आने वाली भीड़ को देखते हुए स्टेशन परिसर में होल्डिंग एरिया भी बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से यात्रियों को चरणबद्ध तरीक़े से प्लेटफ़ार्म पर प्रवेश दिया जाएगा। गांधी नगर जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य अंतिम चरण में है। महाप्रबंधक ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हो रहे इन पुनर्विकास कार्यों का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने यात्रियों के सुगम आवागमन, उपलब्ध स्थान का उपयुक्त प्रयोग, सुव्यवस्थित पार्किंग, प्रवेश एवं निकास मार्ग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग तथा साइनेज के संबंध में दिशा निर्देश दिए।इसके साथ ही त्योहारों के दौरान संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर कार्यरत सभी संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए । कर्मचारियों को सतर्क रहते हुए यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित बनाए रखने, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने कुमार सतीजा, प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त, श्री जे. एस. लाकरा, प्रमुख मुख्य इंजीनियर सहित मुख्यालय एवं जयपुर मंडल के कई अधिकारी सम्मिलित हुए।



पति की मौत के बाद महिला और बच्चों पर टूटा संकट, आपसी विवाद में घर से बेघर करने का आरोप

गोपाल गुप्ता। सिटी चीफ

जयपुर। आगरा रोड स्थित प्रेम नगर पुलिया क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक महिला और उसके बच्चों को कथित तौर पर घर से बेघर करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला के पति की मृत्यु के बाद परिवार के अन्य लोगों द्वारा महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट एवं परेशान किया जा रहा है।पीड़ित महिला का आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद वह अपने बच्चों के साथ पहले से ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है। ऐसे में आपसी विवाद के चलते उसे घर से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ भी मारपीट किए जाने की बात सामने आई है।मामले ने महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पति की मृत्यु के बाद बेसहारा हुए परिवार को इस तरह परेशान क्यों किया जा रहा है? क्या महिला और उसके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है?

FSDA की बड़ी कार्रवाई वाराणसी में 23 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर लिए गए 18 सैंपल



डॉ उदय शंकर भगत। सिटी चीफ

वाराणसी। त्योहारों और आम दिनों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है विभाग की टीम ने सोमवार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 23 प्रतिष्ठित खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया इस दौरान गुणवत्ता की जांच के लिए 18 विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने सैंपल संकलित किए गए हैं जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला खुड्डु भेजा जा रहा है जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने शहर के कई व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में एक साथ शिकंजा कसा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को जिन क्षेत्रों में छापेमारी की गई उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं चेतगंज भरलाई नवलपुर शिवपुर सेनपुरा अखरी बाइपासऔर अन्य आसपास के इलाके मे छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों पर बिकने वाले सामान की साफ-सफाई और गुणवत्ता को परखा इस दौरान टीम ने मिलावट की आशंका के आधार पर कुल 18 सैंपल भरे जिनमें मुख्य रूप से बेसन के लड्डू सोनपापड़ी छेना की मिठाइयाँ शुद्ध सरसों का तेल

सॉस शामिल हैं इन सभी नमूनों को सील कर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा जा रहा है सहायक आयुक्त द्वितीय कौशलेंद्र शर्मा ने इस बड़ी कार्रवाई के बाद दो टूक शब्दों में कहा कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा मिलावट किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थों में मिलावट या गड़बड़ी की आशंका हो तो इसकी शिकायत विभाग में दर्ज कराएं शिकायत पुख्ता मिलने पर संबंधित दुकानदारों अ

नए भारत में छात्राओं की भूमिका विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन

डॉ उदय शंकर भगत। सिटी चीफ

वाराणसी। राजातालाब (उ.प्र.). राष्ट्रीय महिला उत्थान समिति के तत्वावधान में सोमवार को सुबह 11 बजे ज्ञान दायनी महिला महाविद्यालय अकेलवां में शिक्षा जीवन के लिए जीवन वतन के लिए थीम पर नए भारत में छात्राओं की भूमिका÷ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में सावित्री बाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने अपने संबोधन में कहा कि नए भारत का निर्माण बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के बिना संभव नहीं है उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले ने जिस शिक्षा की अलख जगाई थी आज उसी के बल पर हमारी बेटियां हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। बेटियों को शिक्षित होना जागरूक होना और राष्ट्र निर्माण में बढ़-चढ़कर भाग लेना होगा विशिष्ट मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता भाजपा उत्तर प्रदेश एवं पूर्व मेयर वाराणसी कौशलेन्द्र पटेल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी सशक्तीकरण केवल नारा नहीं बल्कि संकल्प बन चुका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर लखपति दीदी और ड्रोन दीदी तक योजनाओं ने महिलाओं को नई उड़ान दी है छात्राओं को सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग और राष्ट्रवादी विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आयुषी श्रीमाली का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है इस अपनी भूमिका समझाना और उन्हें राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ना है उन्होंने कहा कि हम ऐसे संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव और कॉलेज कॉलेज तक बेटियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कार्यक्रम का आयोजन भाजपा युवा मोर्चा वाराणसी के महानगर मंत्री श्रीपति मिश्रा एडवोकेट के साथ संयुक्त रूप से किया गया

कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्यपालन एवं पशुपालन विभाग की गतिविधियों की कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने की समीक्षा

संजीव कुमार निगम । सिटी चीफ

शहडोल, कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्यपालन, कृषि अभियांत्रिकी एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पात्र हितग्राहियों और किसानों को समय पर लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मत्स्यपालन गतिविधियों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के बाणसागर जलाशय में 10 हजार केज लगाए जाएंगे। नवंबर माह में दो विभिन्न कंपनियों द्वारा 500-500 केज लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कलेक्टर ने इस गतिविधि को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने मसाला विस्तार योजना के अंतर्गत किसानों को



प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बताया गया कि योजना के तहत जिले के तीन जनपदों के 29 ग्रामों में किसानों द्वारा मसाला धनिया उत्पादन की गतिविधि संचालित की जाएगी।

कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि रासायनिक उर्वरकों एवं बीजों के निरंतर नमूने लेकर प्रयोगशालाओं से उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए। जांच में निम्न गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने किसानों को कतार में बुवाई के प्रति जागरूक करने तथा कृषि अधोसंरचना के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में बताया गया कि जिले में रासायनिक उर्वरक एवं बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अभी तक 2,511 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है तथा 11,261 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इसके साथ ही चना एवं मसूर का 15,943 क्विंटल बीज उपलब्ध है, जिसे किसान सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय कर सकते हैं।प्राकृतिक खेती की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 25 बीआरसी बनाए गए हैं तथा 4,375 किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है। योजना के अंतर्गत सभी बीआरसी को एक-एक लाख रुपये तथा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 4-4 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कलेक्टर ने प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने और अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए।पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने डॉ. भीमराव अंबेडकर डेयरी योजना, आचार्य विद्यासागर योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना तथा मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बैगा हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने, बकरी पालन को प्रोत्साहित करने तथा कृत्रिम गर्भाधान एवं सेक्स्ड सीमेन से गर्भाधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति, उप संचालक कृषि श्री के.एस. यादव, कृषि वैज्ञानिक श्री बी.के. प्रजापति, उपायुक्त सहकारिता श्री अभय सिंह, महाप्रबंधक जिला काकोटे, उप संचालक पशुपालन डॉ. गुप्ता, सहायक संचालक उद्यानिकी सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

उप स्वास्थ्य केन्द्र टेंधा में स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर जारी, सीएमएचओ ने दी वस्तुस्थिति की जानकारी

संजीव कुमार निगम। सिटी चीफ

शहडोल 03 नवंबर 2026- उप स्वास्थ्य केन्द्र टेंधा में एक वर्ष से एएनएम की तैनाती नहीं होने के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने वस्तुस्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उप स्वास्थ्य केन्द्र टेंधा में स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर संचालित की जा रही हैं। यहां पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) श्री पंकज रैदास द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। साथ ही मरीजों की समय-समय पर जांच कर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जा रहा है।

सीएमएचओ डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि उप स्वास्थ्य केन्द्र टेंधा में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद रिक्त होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र पथखई में पदस्थ श्रीमती सीमा वर्मा का अस्थायी संलग्नीकरण टेंधा में किया गया था। शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में सभी संलग्नीकरण समाप्त कर संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर भेजे जाने के फलस्वरूप श्रीमती सीमा वर्मा को पुनः उप स्वास्थ्य केन्द्र पथखई भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि उप स्वास्थ्य केन्द्र टेंधा में सीएचओ श्री पंकज रैदास की पदस्थापना है और उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, टीकाकरण सहित नियमित स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

आखिर कब और कहां होगी टक्कर भारत-PAK के बीच खेले जाएंगे 10 वनडे मुकाबले!



भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत की शुरुआत सबसे पहले अंडर-19 एशिया कप से होने जा रही है, जिसका पहला मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाना है. अगर दोनों युवा टीमें अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक का सफर तय करती हैं तो इस टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान की दो बार भिड़ंत हो सकती है.

क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी राइवलरी यानी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. आने वाले एक साल के भीतर दोनों टीमें कुल 10 वनडे मुकाबलों में आमने-सामने हो सकती हैं. इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत में भारत के युवा और विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर पूरी तरह गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हैं. दोनों ही खिलाड़ी इस महीने यानी नवंबर में पाकिस्तान से टक्कर लेंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत की शुरुआत सबसे पहले अंडर-19 एशिया कप से होने जा रही है, जिसका पहला मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाना है. अगर दोनों युवा टीमें अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक का सफर तय करती हैं तो इस टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान की दो बार भिड़ंत हो सकती है. इस महीने हो सकती है चार बार भिड़ंत? इसके अलावा राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए भी हाल ही में टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे युवा धुरंधर खेलते नजर आएंगे. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 22 नवंबर को तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा. अगर यहां भी दोनों टीमें फाइनल (29 नवंबर) में पहुंचती हैं तो इस टूर्नामेंट में भी दो बार आमना-सामना तय है. इस तरह इन शुरुआती टूर्नामेंट्स में कुल 4 बार दोनों टीमें टकरा सकती हैं. एशिया कप के खेले जा सकते हैं 3 मुकाबले अगले साल जून और जुलाई के दौरान एशिया कप का आयोजन होना है. चूंकि अगला साल वनडे वर्ल्ड कप का है, इसलिए एशिया कप भी वनडे फॉर्मेट में ही खेला जाएगा. हालांकि अभी तक आधिकारिक शेड्यूल और ग्रुप्स का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन परंपरा के मुताबिक दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा. एशिया कप के मौजूदा फॉर्मेट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान की टीमें पहले ग्रुप स्टेज में, फिर सुपर-4 स्टेज में और यदि दोनों ने बेहतरीन खेल दिखाया तो फाइनल में यानी कुल 3 बार एक-दूसरे से टकरा सकती हैं. वनडे वर्ल्ड कप 2027 में हो सकते हैं 3 मुकाबले क्रिकेट का महाकुंभ यानी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है. इस मेगा इवेंट के नए और रोमांचक फॉर्मेट को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज, नए सुपर-7 स्टेज और फिर नॉकआउट या फाइनल मुकाबलों को मिलाकर कुल 3 बार महा-टक्कर देखने को मिल सकती है.



इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान

मैदान पर अब नहीं दिखेगा मैक्सवेल का जलवा

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. सोमवार देर रात उन्होंने अपने फैसले की जानकारी दी. मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 286 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, जिसमें 7226 रन बनाने के साथ 136 विकेट भी हासिल किए. वह 2015 और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे. इसके अलावा 2021 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में भी शामिल थे.

मैक्सवेल ने %फाइनल वर्ल्ड पॉडकास्ट% पर अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला थोड़ा दुखद जरूर है, लेकिन इसकी उम्मीद पहले से थी. उन्होंने कहा, %इंटरनेशनल क्रिकेट और विक्टोरिया के लिए घरेलू 50 ओवर और चार दिवसीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करते हुए थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन यह फैसला लगभग तय था. रेड-बॉल क्रिकेट से विदाई शायद किसी को हैरान नहीं करेगी.

मैक्सवेल ने आगे बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन के साथ इस फैसले को लेकर पहले भी कई बार बातचीत हुई थी. टी20 वर्ल्ड कप के बाद उनके भविष्य पर चर्चा हुई, लेकिन किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया. टीम प्रबंधन भविष्य की तैयारी में जुटा था और नए खिलाड़ियों को मौका दे रहा था. बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में भी युवा खिलाड़ियों को आजमाया गया, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया.

मैक्सवेल के करियर की सबसे यादगार पारी 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ आई थी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 91 रन पर 7 विकेट गंवा चुका था. टीम की हार लगभग तय नजर आ रही थी, लेकिन मैक्सवेल ने अकेले दम पर मैच का रुख पलट दिया.उन्होंने 128 गेंदों पर नाबाद 201 रन ठोक दिए. इस दौरान उनके बल्ले से 21 चौके और 10 छक्के निकले. खास बात यह थी कि ऐंठन के कारण मैक्सवेल ज्यादातर समय ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहे थे. इसके बावजूद उन्होंने कप्तान पैट कमिंस के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए नाबाद 202 रनों की साझेदारी कर दी.कमिंस ने 68 गेंदों पर नाबाद 12 रन बनाए, जबकि मैक्सवेल ने तूफानी दोहरा शतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी. ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 19 गेंद शेष रहते जीत लिया. मैक्सवेल की इस पारी को वनडे क्रिकेट की सबसे असाधारण पारियों में गिना जाता है.मैक्सवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले जून 2025 में वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. भारत के खिलाफ दुबई में खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल उनका आखिरी वनडे मुकाबला था.



तमिलनाडु में आयोजित डब्ल्यूटीए 250 चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में सर्बिया की टेनिस खिलाड़ी तेओदोरा कोस्तोविच स्पेन की ओक्साना सेलेखमेतेवा के खिलाफ दमदार खेल दिखाती हुई. कोर्ट पर दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबले में जीत के लिए जोरदार संघर्ष देखने को मिला.

IPL का सबसे बड़ा फेरबदल प्रीति जिंटा की टीम से जुड़ेंगे हार्दिक पंड्या?

आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन और रिटेंशन डेडलाइन से ठीक पहले ट्रांसफर मार्केट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई इंडियंस के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या आगामी सीजन में प्रीति जिंटा की सह मालकिन वाली पंजाब किंग्स की लाल जर्सी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच इस ट्रेड डील को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और माना जा रहा है कि यह ब्लॉकबस्टर डील लगभग फाइनल हो गई है. ऐसे में जल्द ही इस बात की आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है.



स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट के मुताबिक रिकी पोंटिंग के मार्गदर्शन वाली पंजाब किंग्स हार्दिक पंड्या जैसे मैच-विनिंग ऑलराउंडर को हर हाल में अपनी टीम में शामिल करना चाहती है. लेकिन हार्दिक को हासिल करने के लिए पंजाब को एक बहुत बड़ा त्याग करना पड़ रहा है. इस स्वैप डील (अदला-बदली) के तहत भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज विष्णु विनोद मुंबई इंडियंस का रुख करेंगे. दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रेड का पहला प्रस्ताव मुंबई इंडियंस के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से आया था, जिसके बाद पंजाब किंग्स इस डील पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई. मुंबई को अपनी टीम में जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए एक वर्ल्ड-क्लास भारतीय पेसर और एक भरोसेमंद विकेटकीपर की सख्त जरूरत थी, जो इस डील से पूरी होती दिख रही है.

मनोरंजन

टीवी एक्ट्रेस ने समंदर किनारे शानदार पोज दिए

बीच पर अनुष्का का बोल्ड अंदाज



टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन अपनी बोल्ड तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं. 24 साल की एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बीच वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने 24 साल की उम्र में बड़ा नाम कमा लिया है. वह इंडिया ही नहीं साउथ कोरिया में भी फेमस हैं. अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर अपनी बोल्ड तस्वीरें पोस्ट की हैं. इनमें वो समंदर किनारे चिल कर रही हैं. एक्ट्रेस ने मल्टीकलर बिकिनी पहनी है. वह स्वैग में पोज दे रही हैं. ब्लैक सनग्लासेज पहनकर वो टशन दिखा रही हैं. अनुष्का सेन ने कभी जुल्फें लहराते हुए तो कभी रेत पर लेटकर पोज दिए. एक्ट्रेस की बोल्ड अदाओं पर फैंस फिदा हैं. उनकी टोन्ड फिगर तस्वीरों में दिखती है. उनकी खूबसूरती से लोगों की नजरें नहीं हट रही हैं. पोस्ट में अनुष्का ने खुद को %बीच बेबी% बताया है. फैंस बोले- फायर, ग्लैमरस और स्टनिंगफैंस ने उनकी बोल्ड फोटोज पर कमेंट कर- फायर, ग्लैमरस और स्टनिंग लिखा है. अनुष्का का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो समंदर की लहरों के आगे खड़ी होकर चिल करती दिख रही हैं. अनुष्का एक्ट्रेस होने के साथ सोशल मीडिया सेंसेशन भी हैं. उनके 37.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह छोटी उम्र से शोबिज में काम कर रही हैं. उन्होंने हिंदी शो बालवीर, झांसी की रानी, खतरों के खिलाड़ी 11 में काम किया है. ओटीटी पर भी वो एक्टिव हैं.

सिंगर ने बताया कैसे दो साल में घटाया 130 किलो वजन अदनान सामी का गजब ट्रांसफॉर्मेशन

सिंगर अदनान सामी अपनी शानदार आवाज के साथ-साथ अपने जबरदस्त वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी जाने जाते हैं. एक वक्त ऐसा था जब उनका वजन इतना बढ़ गया था कि उनके लिए ठीक से चलना-फिरना तक मुश्किल हो गया था. उन्हें उठने के लिए दो लोगों की मदद लेनी पड़ती थी. यहां तक कि वो बिस्तर पर लेटकर सो भी नहीं पाते थे. करियर की शुरुआत में अदनान सामी का वजन 230 किलो के आसपास था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और करीब दो साल की कड़ी मेहनत के बाद 130 किलो वजन कम कर लिया. अब सिंगर ने अपने इस मुश्किल सफर के बारे में खुलकर बात की है. अदनान सामी हाल ही में अनट्रिगर्ड विद अमीन जैज पॉडकास्ट में पहुंचे थे. यहां उन्होंने बताया कि वजन कम करने के बाद भी लोगों ने उनके ट्रांसफॉर्मेशन पर सवाल उठाए थे. कई लोगों का कहना था कि उन्होंने लिपोसक्शन या कोई दूसरी सर्जरी कराई है. इस पर अदनान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर उन्होंने इतने ज्यादा वजन के लिए लिपोसक्शन कराया होता तो डॉक्टर को वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़ती. दो साल तक चला वजन कम करने का सफर अदनान ने बताया कि उनका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो खुद से खड़े तक नहीं हो पाते थे. उन्हें उठाने के लिए दो लोगों की मदद लेनी पड़ती थी. वो अपनी इस हालत को लोगों से छिपाकर रखते थे. वो पब्लिक के सामने हमेशा खुश रहने और खाने का मजा लेने वाली अपनी छवि बनाए रखते थे, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा. सिंगर ने कहा- मैं एयरपोर्ट पर एक नॉर्मल व्हीलचेयर में भी फिट नहीं हो पाता था. मेरे लिए खासतौर पर कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर बनवाई गई थी. कार में बैठने के लिए मेरा ड्राइवर मेरे पैर उठाकर अंदर रखता था. यहां तक कि मैं सीधे बिस्तर पर लेटकर सो भी नहीं सकता था. छाती पर जमे फैट के दबाव की वजह से मुझे सांस लेने में परेशानी होती थी. इसलिए मैं सोफे पर बैठकर सोता था. अदनान ने आगे बताया कि कॉन्सर्ट के दौरान भी उन्हें काफी दिक्कत होती थी. स्टेज तक पहुंचने के लिए थोड़ी दूरी चलने के बाद उन्हें करीब 10 मिनट बैठकर सांस लेनी पड़ती थी. वो अपना पूरा कॉन्सर्ट पियानो के सामने बैठकर करते थे. परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी वो इतने थक जाते थे कि अगले 15 मिनट तक उनसे कोई बात नहीं कर सकता था. डाइट में किया बदलाव



अदनान बताते हैं कि वजन कम करने के लिए उन्होंने अपनी डाइट में काफी बदलाव किया था. उन्हें ब्रेड, चावल, चीनी, तेल और शराब से पूरी तरह दूरी बनाने के लिए कहा गया था. उनकी डाइट में मुख्य रूप से प्रोटीन वाली चीजें शामिल थीं. उन्होंने बताया- शुरुआत में मेरे लिए चलना भी बेहद मुश्किल था. डॉक्टरों की सलाह पर मैंने थोड़ी-थोड़ी देर चलना शुरू किया. गर्मी के मौसम में मैं ह्यूस्टन के शॉपिंग मॉल में जाकर चलता था, क्योंकि वहां एसी की सुविधा थी. कुछ कदम चलने के बाद मैं बैठ जाता था और फिर दोबारा चलना शुरू करता था. इसी दौरान मुझे एक टी-शर्ट पसंद आई थी, जो तब मेरे मौजूदा साइज से काफी छोटी थी. मेरी मां ने भी मुझे समझाया था कि अभी वो टी-शर्ट मुझे फिट नहीं आएगी, लेकिन मैंने उसे खरीद लिया. मैंने तय कर लिया था कि वजन कम करके मैं इसी टी-शर्ट को पहनूंगा. मैं रात के तीन बजे भी उठकर चेक करते थे कि टी-शर्ट मुझे फिट आ रही है या नहीं. आखिरकार साल 2007 में वो टी-शर्ट मुझे फिट आ गई. मोटापे को बीमारी मानते हैं अदनान बातचीत के दौरान अदनान ने मोटापे को लेकर लोगों की सोच पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि लोग अक्सर मोटे इंसान को उसके खानपान के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता. कई बार इसके पीछे जेनेटिक्स और शरीर की बनावट जैसे कारण भी हो सकते हैं. उन्होंने कहा- मोटापे को एक बीमारी की तरह समझने की जरूरत है. फिल्मों में भी पहले मोटे लोगों का मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें हमेशा हंसमुख किरदारों में दिखाया जाता था. मुझे इस तरह के फैट जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं हैं. किसी की शारीरिक स्थिति को कॉमेडी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए. अब कैसे खुद को फिट रखते हैं अदनान सामी? अदनान सामी ने बताया कि वजन कम करने के बाद भी उन्हें खाने का उतना ही शौक है. फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब वो हर चीज सीमित मात्रा में खाते हैं. पहले वो अकेले पूरी बिरयानी खा जाते थे, लेकिन अब कुछ निवाले खाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं. उन्होंने कहा- अगर मुझे लड्डू खाने का मन करता है तो मैं उसका आधा या एक छोटा टुकड़ा खा लेता हूं. मैं खुद को किसी चीज से पूरी तरह वंचित नहीं रखता, बल्कि खाने की मात्रा पर ध्यान देते हैं. मेरे डायटीशियन ने समझाया था कि वजन कम करने के बाद भी मुझे पूरी जिंदगी अपने वजन पर नजर रखनी होगी. उनके मुताबिक, शरीर और त्वचा एक बार स्ट्रेच हो जाए तो दोबारा पहले जैसी नहीं होती. इसलिए थोड़ी सी लापरवाही से वजन फिर बढ़ सकता है. मुझे एक्स्ट्रा स्किन हटाने के लिए सर्जरी कराने की सलाह भी दी गई थी, लेकिन मैंने उसकी हिम्मत नहीं जुटाई.

KBC में बिग बी ने सुनाया शादी के बाद का किस्सा अमिताभ को जया बुलाती थीं लंबू जी



मेगास्टार अमिताभ बच्चन रियलिटी शो %कौन बनेगा करोड़पति% की जान बन चुके हैं. बिग बी शो में सिर्फ कंटेस्टेंट्स संग सवाल ही नहीं पूछते, बल्कि अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से और एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं. अब अमिताभ ने शो में पत्नी जया बच्चन से जुड़ा दिलचस्प सीक्रेट खोला है.

कौन बनेगा करोड़पति% शो में अमिताभ बच्चन ने अपनी शादी से जुड़ा मजेदार किस्सा सुनाया. बिग बी ने बताया कि शादी के बाद जया बच्चन प्यार से उन्हें लंबू जी कहती थीं, लेकिन उनके पिता हरिवंश राय बच्चन को जया का उन्हें लंबू जी कहना पसंद नहीं था. उनके पिता ने जया को इस चीज के लिए टोक दिया था और उन्हें लंबू जी कहने से मना किया था.

दिवाली स्पेशल एपिसोड में रणबीर कपूर से बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा- कई सालों तक वो (जया बच्चन) हमको लंबू जी बोला करती थीं. फिर उसके बाद उन्हें मना किया गया. बाबू जी ने उन्हें कहा था ऐसे मत बोलो...या तो नाम लो या फिर कुछ और बोलो. उन्होंने फिर हमें नाम से बुलाना शुरू किया.

रणबीर ने अमिताभ बच्चन को बताया कि जब भी वो उन्हें और जया बच्चन को देखते हैं, तो उन्हें अपनी और आलिया की हाइट को लेकर भी कई विचार आते हैं. रणबीर बोले- मेरे जहन में वो तस्वीर हमेशा आती है कि मैं अमित जी जैसा थोड़ा लंबा हूं और आलिया भी जया आंटी जैसी हैं, तो हाइट का अंतर तस्वीरों में अच्छा लगेगा.

बॉम्बे हाईकोर्ट का बीएमसी को सुझाव

दीया का वीडियो दोबारा पोस्ट करें

बीएमसी के प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान से अभिनेत्री दीया मिर्जा का वीडियो हटाए जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने इसे परेशान करने वाला कदम करार दिया है. साथ ही वीडियो दोबारा पोस्ट करने का सुझाव दिया. कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण जागरूकता जैसे सामाजिक कार्यों में गुटबाजी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. मुंबई की साझा संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए.दरअसल, बीएमसी को पॉल्यूशन-फ्री दिवाली कैंपेन का वह वीडियो हटाना पड़ा, जिसमें एक्ट्रेस दीया मिर्जा थीं. शहर की मेयर रितु तावड़े और बीजेपी चीफ अमित साटम ने उनके शामिल होने पर आपत्ति जताई थी.कोर्ट ने सुझाव दिया कि कैंपेन के कंटेंट को फिर से लगाना आदर्श होगा, ताकि संविधान में लोगों का भरोसा बहाल हो सके, क्योंकि मुंबई शहर साथ मिलकर रहने की भावना पर टिका है और किसी भी अनुचित टिप्पणी से यह संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए.बीजेपी नेताओं का नाम लिए बिना, कोर्ट ने कहा, हम उन लोगों की टिप्पणियों से परेशान हैं जिन्होंने उन सेलिब्रिटीज के बारे में बातें कहीं, जिन्होंने बीएमसी के जन अभियान के काम में हिस्सा लिया और मदद की. यह काम पटाखे फोड़ने से होने वाले शोर और वायु प्रदूषण के बुरे असर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए थाकोर्ट ने कहा कि हमारी राय में, बीएमसी ने बहुत असरदार कदम उठाए और उन सभी (सेलिब्रिटीज) ने साथ मिलकर रहने का संदेश दिया. हमारा पक्का मानना है कि जब इतने गंभीर भाव से ऐसा काम किया गया, तो उसमें गुटबाजी की कोई जगह नहीं थी.हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा है कि दीया मिर्जा वाले वीडियो को फिर से लगाना आदर्श होगा और यह फैसला बीएमसी पर छोड़ दिया गया है. जस्टिस जीएस कुलकर्णी ने कहा, जब हम ऑर्डर पास करते हैं, तो क्या उसमें ऐसा कोई नियम होता है कि ङ्क व्यक्ति प्रचार करने के लिए योग्य नहीं होगा. कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आगे आ रहा है





पंजाब में 2027 चुनाव से पहले भाजपा-अकाली दल के गठबंधन की अटकलें तेज

चंडीगढ़. पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के दोबारा साथ आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. राजनीतिक गलियारों में दोनों दलों के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत की अटकलें हैं. हालांकि, किसी भी पार्टी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

सूत्रों के मुताबिक, संभावित समझौते में मुख्यमंत्री पद अकाली दल के पास रह सकता है, जबकि भाजपा 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. बाकी 67 से 72 सीटों पर अकाली दल के उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा है.1997 से 2017 तक दोनों दल गठबंधन में रहे थे. इस दौरान भाजपा 23 और अकाली दल शेष विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ता था. इस बार भाजपा अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अधिक सीटों की मांग कर सकती है.चर्चा है कि दिवाली के बाद बठिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान गठबंधन का ऐलान हो सकता है. हालांकि, रैली और घोषणा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 के चुनाव के बाद पंजाब में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया था.गठबंधन की स्थिति में केंद्र सरकार में भी नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं. अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल की मोदी मंत्रिमंडल में वापसी की अटकलें हैं. वह सितंबर 2020 तक केंद्रीय मंत्री थीं. कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल के एनडीए से अलग होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. हालांकि, उनकी वापसी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गठबंधन की संभावनाओं को खारिज नहीं किया है. उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बताते हुए समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन के रास्ते खुले होने की बात कही थी. अकाली दल से अलग हुए बागी गुटों की संभावित गठबंधन में भूमिका भी स्पष्ट नहीं है. ऐसे में सीटों के बंटवारे और सहयोगी दलों को लेकर अंतिम तस्वीर सामने आना बाकी है.

गुजरात में एमपी के 2 युवकों की जिंदा जलाकर हत्या, नाराज हुए जीतू पटवारी, उच्चस्तरीय जांच की मांग

भोपाल/अमरेली. गुजरात के अमरेली जिले में एमपी के दो युवकों की बीती रात मौत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गुजरात के अमरेली जिले में मप्र के दो युवकों रवि बघेल (16) और नितिन पचाया (21) को गाड़ी में जिंदा जला दिए जाने की हृदयविदारक घटना की जानकारी मिली. दोनों रोजगार की तलाश में गुजरात गए थे. मप्र के सीमावर्ती जिलों से हजारों आदिवासी भाई-बहन रोजी-रोटी की तलाश में गुजरात जाते हैं.

ऐसे में वहां हमारे नागरिकों की सुरक्षा का सवाल बेहद महत्वपूर्ण है. विशेष रूप से तब जब प्रधानमंत्री गुजरात को मॉडल बताते हैं. मप्र के मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार से तत्काल बात कर इस दोहरे हत्याकांड की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच सुनिश्चित करवाएं. साथ ही गुजरात में काम कर रहे मध्य प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा की ठोस व्यवस्था हो.

बता दें कि बीते दिन 60,000 रुपये के लेन-देन के



विवाद के चलते गुजरात के अमरेली जिले में मध्यप्रदेश के दो युवकों को गाड़ी समेत जिंदा जला दिया गया. घटना के पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. पुलिस को जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि घटना के पीछे 60 हजार रुपए का लेन-देन का विवाद है. हालांकि कई लोगों से पूछताछ के बाद ही असली वजह का खुलासा होगा. जानकारी मिली है कि विपेन सिंह ने विनोद को अपनी गाड़ी बेच दी थी. इसके बाद उसने कमलेश से कहा था कि वह अपने पैसे विनोद से ले लें. आरोप है कि कमलेश ने विनोद की गैरमौजूदगी में गाड़ी ले ली थी. जब इस बात का पता चला तो वह नाराज हो गया. पुलिस के अनुसार, इसी रंजिश में उसने अपने साथी राजू के साथ मिलकर गाड़ी में आग लगा दी और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी में पता चला है कि मरने वाले दोनों मजदूर खेत में मजदूरी करते थे. पेसे देने में देरी होने के कारण शिकायतकर्ता आरोपियों की जानकारी के बिना वहीं से गाड़ी लेकर चला गया. इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया. पुलिस के सामने विनोद ने वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली है. विनोद और राजू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

राजस्थान- श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट, दो सीमेंट ब्लॉक टूटे; चार ट्रेनें रद्द

श्रीगंगानगर. राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलखंड पर मंगलवार रात करीब 9:45 बजे धमाका हुआ. विस्फोट से रेलवे पटरी के नीचे लगे सीमेंट के दो ब्लॉक पूरी तरह टूट गए और पटरियों के बीच करीब दो फीट गहरा गड्ढा हो गया. धमाके की आवाज करीब 200 मीटर दूर तक सुनाई दी. घटना से पहले रात करीब 9 बजे इस ट्रैक से एक पैसेंजर ट्रेन गुजरी थी.

रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस, आईबी, सीआईडी और एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) की टीमें मौके पर पहुंचीं. एहतियातन बुधवार सुबह तक इस रेलखंड पर यातायात बंद रखा गया. इसके चलते बुधवार को इस रूट की चार ट्रेनें रद्द कर



दी गईं. रेलवे की टीम मंगलवार देर रात करीब दो बजे घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की गई.

रात करीब दो बजे आईबी और सीआईडी की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. इसके करीब 15 मिनट बाद एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे. श्रीगंगानगर के एसपी हरिशंकर ने बताया कि विस्फोट की तीव्रता और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच की जा रही है. एफएसएल की टीम घटनास्थल से नमूने लेकर उनका परीक्षण करेगी.

रामसिंहपुर थाना प्रभारी राम प्रताप के मुताबिक, मंगलवार रात 8:30 बजे अनूपगढ़ जंक्शन से सूरतगढ़ के लिए ट्रेन रवाना हुई थी. रात करीब नौ बजे ट्रेन 50 जीबी गांव के आसपास से गुजरी. इसके लगभग 45 मिनट बाद रेलवे पटरी पर धमाका हुआ. आवाज सुनकर करीब 200 मीटर दूर स्थित ढाणी में रहने वाले ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रात करीब 11 बजे पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे.

बहराइच मेले में बड़ा हादसा, जलपरी शो का टैंक फटा, 4 बच्चों समेत 15 घायल, सिर-चेहरे में कांच घुसे

बहराइच. उत्तर प्रदेश के बहराइच मेले में जलपरी शो का पानी से भरा टैंक अचानक फट गया. हादसा जिस वक्त हुआ, उस वक्त 40 लोग शो देख रहे थे. टैंक फटने से 20 हजार लीटर पानी झटके से बाहर आया. पानी के प्रेशर से कांच की दीवार टूट गई. शो में अचानक भगदड़ जैसे हालात हो गए. बच्चे पानी के बहाव में कई मीटर तक बह गए. कांच के टुकड़े चेहरे और सिर में धंस गए. 4 बच्चों समेत 15 लोग घायल हो गए.

पुलिस और आसपास के लोग सभी घायलों को नजदीकी सीएचसी ले गए. वहां से 2 बच्चों को रेफर कर दिया गया. उनके सिर-चेहरे में कांच के कई टुकड़े धंसे हैं. हादसे में एक जलपरी भी घायल हुई है. एसपी सिटी आयुष



विक्रम सिंह ने कहा- मेला कमेटी अध्यक्ष और जलपरी शो संचालक समेत 4 को पुलिस ने हिरासत में लिया है. 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पानी का प्रेशर अधिक होने के कारण टैंक फटा है.

जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर फखरपुर के खालिदपुर गांव में उर्स मेले में सोमवार रात 9 बजे हादसा हुआ. इसमें अर्श (8), बुरुऊ (7), अहद खान (8) और मोहम्मद सादिक (9) ज्यादा घायल हैं. सभी गांव के रहने वाले हैं.

खालिदपुर गांव में हर साल नवंबर में दादा मियां के उर्स में 3 दिवसीय मेला लगता है. इस साल उर्स मेले में पहली बार जलपरी शो लगाया गया. जलपरी शो में एक लड़की मछली जैसी ड्रेस में पानी के टैंकर में करतब दिखाती है. टैंकर करीब 20 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है. इसमें 20 हजार लीटर पानी भरा था. बाहर की ओर कांच की एक दीवार होती है.

फखरपुर के खालिदपुर गांव निवासी सलीम खान ने बताया कि दादामियां के उर्स में सोमवार से मेला शुरू हुआ था. मैं अपने परिवार के साथ मेला देखने गया था. इसमें जलपरी शो भी लगाया गया था.

बिजनेस

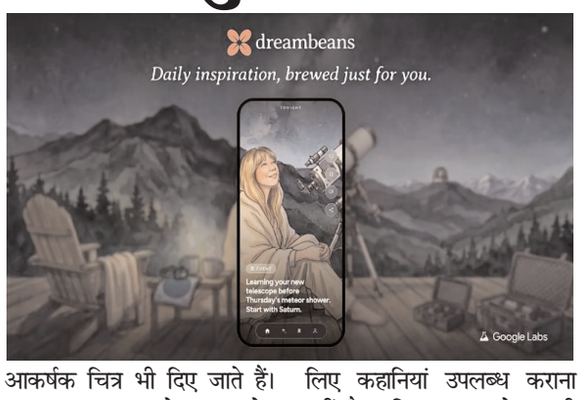
Google का नया AI ऐप Dreambeans लॉन्च, रातभर की डिजिटल गतिविधियों को समझकर सुबह तैयार करेगा पर्सनलाइज्ड कहानियां

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लगातार नए प्रयोग कर रही टेक कंपनी ने भारत में अपना नया प्रयोगात्मक ऐप लॉन्च कर दिया है। यह ऐप यूजर की रोजमर्रा की डिजिटल गतिविधियों और उसकी पसंद को समझकर उसके लिए व्यक्तिगत कहानियां तैयार करता है। इसकी खासियत यह है कि यूजर को सुबह उठने पर अपनी रुचियों, पसंदीदा विषयों और गतिविधियों से जुड़ी आकर्षक चित्रों वाली कहानियां देखने को मिलेंगी। त्रश्शद्दद्यद्य के मुताबिक, यह ऐप यूजर की अनुमति से जुड़े त्रश्शद्दद्यद्य अकाउंट और सेवाओं की जानकारी का विश्लेषण करता है और रातभर काम करके अगली सुबह नई कहानियां तैयार करता है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया की तरह लगातार स्क्रॉल करने के बजाय लोगों को उनकी रुचियों से जुड़ी उपयोगी और रचनात्मक जानकारी उपलब्ध कराना है। को भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के यूजर्स के लिए त्रश्शद्दद्यद्य के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। यह औरदोनों प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

एक प्रयोगात्मक आधारित ऐप है, जो यूजर की डिजिटल गतिविधियों से संबंधित जानकारी को समझकर व्यक्तिगत कंटेंट तैयार करता है। त्रश्शद्दद्यद्य ने इसके काम करने की प्रक्रिया को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा ड्रीम और दूसरा बीन कहलाता है।

ड्रीम प्रक्रिया के दौरान ऐप यूजर की अनुमति से कनेक्ट किए गए ऐप्स और सेवाओं से उपलब्ध जानकारी का रातभर विश्लेषण करता है। इस दौरान उसकी रुचियों, गतिविधियों और संभावित पसंद से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की पहचान की जाती है।

इसके बाद उन जानकारियों के आधार पर छोटी-छोटी कहानियां तैयार करता है, जिन्हें ने बीन्स नाम दिया है। प्रत्येक कहानी के साथ



आकर्षक चित्र भी दिए जाते हैं। इस तरह यूजर को सुबह ऐप खोलने पर अपनी पसंद और रुचियों के अनुसार तैयार किया गया नया कंटेंट मिलता है।

उद्देश्य केवल मनोरंजन के लिए कहानियां उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि यूजर को उसकी पसंद के अनुसार नई गतिविधियों और अनुभवों से जोड़ना भी है। ऐप में ऐसे विषयों से संबंधित सुझाव मिल सकते हैं, जिन्हें यूजर आगे जानना या अनुभव करना चाहता है।इसमें घूमने के लिए नई जगहों की जानकारी, कला और हस्तशिल्प से जुड़ी गतिविधियां, नई चीजें सीखने के सुझाव और अलग-अलग कार्यक्रमों की याद दिलाने वाले रिमाइंडर शामिल हो सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी यूजर की रुचि यात्रा, कला या किसी विशेष गतिविधि में है, तो ऐप उससे संबंधित उपयोगी सुझावों को चित्रों और कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यूजर किसी भी कहानी को खोलकर उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा पसंदीदा कहानी को बुकमार्क करने और दूसरे लोगों के साथ साझा करने का विकल्प भी दिया गया है।

इससे कहानियां केवल लिखित जानकारी तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उनके साथ संबंधित विषयों के अनुरूप चित्र भी दिखाई देंगे। इससे यूजर को कंटेंट समझने और उससे जुड़ने का एक अलग अनुभव मिल सकता है।

ऐसे यूजर्स जो अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीरों को इन कहानियों में शामिल देखना चाहते हैं, उन्हें में फेस ग्रुपिंग का विकल्प चालू करना होगा। इस सुविधा के सक्रिय होने पर ऐप संबंधित तस्वीरों का उपयोग करके व्यक्तिगत कहानियों के लिए चित्र तैयार कर सकता है।

भारत में इस ऐप की पहुंच बढ़ाने के लिए ने इसे 14 भाषाओं में उपलब्ध कराया है। इनमें अंग्रेजी के साथ हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल और उर्दू शामिल हैं।

हिंदी और मराठी जैसी भारतीय भाषाओं का समर्थन इस ऐप को देश के अलग-अलग क्षेत्रों के यूजर्स के लिए उपयोगी बना सकता है। यूजर अपनी पसंद की भाषा में कंटेंट का अनुभव कर सकेंगे।

पांच लाख रुपये से कम में ऑटोमैटिक कार का सपना होगा पूरा, ट्रैफिक की टेंशन छोड़िए इन 5 हैचबैक पर डालिए नजर

शहरों में बढ़ते ट्रैफिक के बीच कार चलाना अब पहले जैसा आसान नहीं रह गया है. सुबह दफ्तर पहुंचने की जल्दी हो या शाम को घर लौटने का समय, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें और बार-बार रुकने-चलने की स्थिति ड्राइविंग को थकाऊ बना देती है. ऐसे में मैनुअल कार चलाने वालों को लगातार क्लच दबाना और गियर बदलना पड़ता है. खासकर भीड़भाड़ वाले रास्तों पर यह काम परेशानी बढ़ा सकता है. यही वजह है कि अब कम बजट में कार खरीदने वाले ग्राहक भी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले विकल्प तलाश रहे हैं. आमतौर पर ऑटोमैटिक कारों को महंगा माना जाता है, लेकिन भारतीय बाजार में कुछ ऐसी हैचबैक भी मौजूद हैं, जिनके चुनिंदा ऑटोमैटिक वेरिएंट की शुरुआती कीमत पांच लाख रुपये के आसपास या उससे कम बताई गई है. इनमें मारुति एस-प्रेसो, रेनो क्विड, मारुति ऑल्टो



च10, मारुति सेलेरियो और मारुति वैगनआर जैसे मॉडल शामिल हैं.

शहरों में ड्राइविंग के दौरान सबसे अधिक परेशानी तब होती है, जब कार को कुछ मीटर चलाने के बाद बार-बार रोकना पड़ता है. मैनुअल ट्रांसमिशन में हर बार क्लच दबाकर गियर बदलना पड़ता है. लंबे ट्रैफिक जाम में यह प्रक्रिया चालक के पैरों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है. ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी एएमटी इस परेशानी को काफी हद तक कम करता है.

एएमटी कार में गियर बदलने का काम सिस्टम अपने आप करता है. चालक को सामान्य परिस्थितियों में क्लच पैडल दबाने की जरूरत नहीं होती. इससे शहर के भीतर रुक-रुककर चलने वाले ट्रैफिक में कार चलाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है. हालांकि एएमटी और पारंपरिक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की तकनीक अलग होती है. एएमटी में मूल रूप से मैनुअल गियरबॉक्स के साथ स्वचालित क्लच और गियर संचालन की व्यवस्था होती है.

कम बजट वाले खरीदारों के लिए यह तकनीक एक व्यावहारिक विकल्प बन सकती है. लेकिन कार चुनते समय केवल कीमत नहीं, बल्कि माइलेज, जगह, सुरक्षा सुविधाएं, सर्विस खर्च और अपने दैनिक इस्तेमाल को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. एस-प्रेसो का ऊंचा डिजाइन और अपेक्षाकृत सीधी बैठने की व्यवस्था चालक को सड़क का बेहतर दृश्य देखने में मदद कर सकती है. संकरी सड़कों और शहर के भीतर पार्किंग की समस्या से जूझने वाले लोगों के लिए इसका कॉम्पैक्ट आकार उपयोगी साबित हो सकता है.

मारुति के अलावा रेनो क्विड भी कम बजट की ऑटोमैटिक हैचबैक के रूप में विचार करने योग्य विकल्प है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.52 लाख रुपये से बताई गई है. इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एएमटी विकल्प उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है.

एप्पल ला रहा घर के काम करने वाला रोबोट, 9 इंच की घूमने वाली स्क्रीन और सेंसर से होगा लैस; 2027 में लॉन्च की तैयारी

टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब स्मार्टफोन और कंप्यूटर के बाद घरों को स्मार्ट बनाने की प्रतिस्पर्धा तेज होती दिखाई दे रही है. इसी दिशा में एप्पल एक ऐसे छोटे घरेलू रोबोट पर काम कर रहा है, जो घर के भीतर मौजूद रहकर आसपास के माहौल को समझ सकेगा और जरूरत के अनुसार कुछ काम अपने आप कर सकेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस में 9 इंच की स्क्रीन होगी, जिसे एक मोटराइज्ड घूमने वाली बांह पर लगाया जाएगा. कैमरे और सेंसर की मदद से यह रोबोट कमरे में मौजूद लोगों, पालतू जानवरों और आसपास रखी वस्तुओं को पहचानने के साथ अपनी गतिविधियां तय कर सकेगा. एप्पल इस डिवाइस को 2027 में अमेरिकी बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है. इसकी संभावित कीमत करीब 1,000 डॉलर बताई जा रही है. हालांकि तकनीकी विकास और सॉफ्टवेयर से जुड़ी चुनौतियों के कारण लॉन्च 2028 तक टलने की संभावना भी जताई गई है.

द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल अपने मौजूदा स्मार्ट डिस्प्ले का अधिक विकसित और रोबोटिक संस्करण तैयार कर रहा है. इसका प्रोटोटाइप 9 इंच की स्क्रीन के साथ देखा गया है. यह स्क्रीन एक ऐसी मोटराइज्ड बांह पर लगी होगी, जो 360 डिग्री तक घूम सकेगी. इससे डिवाइस कमरे में मौजूद व्यक्ति की दिशा में अपनी स्क्रीन घुमा सकेगा और अलग-अलग स्थानों से इसे देखा जा सकेगा.

इस रोबोट की सबसे महत्वपूर्ण खासियत इसके कैमरे और सेंसर होंगे. इनकी मदद से यह अपने आसपास की गतिविधियों को समझने और परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकता है. उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करेगा, तो रोबोट अपने आप लाइट चालू कर सकता है. इसी तरह घर में मौजूद पालतू जानवरों की गतिविधियों को पहचानकर उनके रास्ते से हटने या उन्हें हल्के तरीके से रास्ता देने जैसे काम भी कर सकता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिवाइस आसपास रखी वस्तुओं और बाधाओं को पहचानते हुए अपनी स्थिति बदल सकेगा. इसका उद्देश्य घर के भीतर बिना टकराए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना और जरूरत के अनुसार स्क्रीन को उपयोगकर्ता की ओर मोड़ना है.

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल सामने आई जानकारियां विकासाधीन प्रोटोटाइप और रिपोर्ट पर आधारित हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि लॉन्च के समय रोबोट में बताए गए सभी फीचर्स उपलब्ध होंगे या नहीं. एप्पल की ओर से इसकी कार्यक्षमता को लेकर कोई आधिकारिक विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, डिवाइस का हार्डवेयर डिजाइन काफी समय पहले तय किया जा चुका है, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर फीचर्स को लेकर कंपनी के भीतर चर्चा जारी है. एप्पल की अलग-अलग टीमें इस बात पर विचार कर रही हैं कि पहली पीढ़ी के रोबोट में कौन-कौन सी सुविधाएं दी जानी चाहिए और किन फीचर्स को भविष्य के मॉडल के लिए सुरक्षित रखा जाए.

इसका अर्थ है कि कंपनी केवल स्क्रीन और मोटराइज्ड आर्म वाला उपकरण तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है, जो घर के वातावरण के अनुरूप काम कर सके. कैमरे और सेंसर से मिलने वाली जानकारी को समझना, उपयोगकर्ता की जरूरत पहचानना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना इसके सॉफ्टवेयर का अहम हिस्सा हो सकता है.

रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि दूसरी पीढ़ी के मॉडल को लेकर भी कंपनी के भीतर चर्चा शुरू हो चुकी है.

स्वामी, प्रकाशक एव मुद्रक श्रीमती ज्योति मिश्रा द्वारा काम्पेक प्रिंटर्स प्रा.लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45 ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान संपादक-आशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं-0731-4202569 फैक्स नं-0731-4202569